राष्ट्रीय छात्रशक्ति

वर्ष 46 ■ अंक 05 ■ अगस्त-सितम्बर 2024 ■ ₹10 ■ पृष्ठ 40

अराजकता के घेरे में 'सोनार बांग्ला'

पारसनाथ : केंद्रीय कार्यसमिति बैठक का उद्घाटन करते हुए अभाविप के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. राजशरण शाही, महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल, संगठन मंत्री आशीष चौहान एवं अन्य।

लखनऊ : अभाविप आयाम मेडिविजन के सातवें राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए उत्तर प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री बृजेश पाठक, अभाविप के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. राजशरण शाही, मंत्री वीरेन्द्र सोलंकी, मेडिविजन संयोजक डा. अभिनंदन बोकरिया एवं अन्य।

राष्ट्रीय
छात्रशक्ति
शिक्षा-क्षेत्र की प्रतिनिधि-पत्रिका

वर्ष 46, अंक 05
अगस्त-सितम्बर 2024

संपादक
आशुतोष भटनागर
संपादक-मण्डल :
संजीव कुमार सिन्हा
अवनीश सिंह
अभिषेक रंजन
अजीत कुमार सिंह

संपादकीय पत्राचार :
राष्ट्रीय छात्रशक्ति
26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नई दिल्ली - 110002.
फोन : 011-23216298
www.chhatrashakti.in
rashtriyachhatrashakti@gmail.com
www.facebook.com/Rchhatrashakti
www.twitter.com/Rchhatrashakti
www.instagram.com/ Rchhatrashakti

स्वामी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक **राजकुमार शर्मा** द्वारा 26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, आई.टी.ओ. के निकट, नई दिल्ली - 110002 से प्रकाशित एवं ओशियन ट्रेडिंग कं., 132 एफ. आई. ई., पटपड़गंज इण्डस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली-110092 से मुद्रित। **संपादक** *पीआरबी अधिनियम के तहत समाचारों के चयन के लिए जिम्मेवार।

अबकी बार

05 **अराजकता के घेरे में 'सोनार बांग्ला'**

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हो रही हिंसा, उत्पीड़न एवं अत्याचार के विरोध में देश की राजधानी दिल्ली से लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में धरना-प्रदर्शन किए जा...

संपादकीय	04
बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिन्दुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे सरकार : अभाविप	10
Annihilation of Hindus in Bangladesh	11
अजमेर बलात्कार कांड में छह अभियुक्तों को आजीवन कारावास	14
'संडे फॉर बीएचयू' अभियान के 50 रविवार पूरे	15
परिस्थितियों के कारण नहीं बदलनी चाहिए संगठन की दिशा : डा. भागवत	16
पुण्यश्लोक देवी अहिल्याबाई	18
प्रदर्शन कर रहे अभाविप कार्यकर्ताओं पर पुलिस का लाठीचार्ज	21
लापरवाही और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई तीन विद्यार्थियों की जिंदगी	22
जेएनयू में स्थापित होंगे हिन्दू, बौद्ध और जैन धर्म अध्ययन केंद्र	23
पारंपरिक भारतीय खेल संस्कृति को बढ़ावा देने की आवश्यकता	24
ओलंपिक में भारत ने हासिल किए छह पदक	27
देश में शैक्षिक सर्वेक्षण कराएगी अभाविप	28
डूसू कार्यालय पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का हमला	29
कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने की आवश्यकता	30
मेधावी छात्रों को अभाविप ने किया सम्मानित	31
'विश्व में परचम लहराएं चिकित्सा विद्यार्थी'	32
कांवड़ियों के लिए सेवा शिविर	34
छात्राओं में कौशल विकास के लिए सर्जना निखार शिविर	35
ममता राज में प्रशिक्षु महिला डाक्टर की निर्मम हत्या	36
महिलाओं के लिए निर्मम पश्चिम बंगाल	37
न्यायमूर्ति हेमा समिति ने वामपंथी शासन के कु-कर्मों को किया उजागर	38

वैधानिक सूचना : राष्ट्रीय छात्रशक्ति में प्रकाशित लेख एवं विचार तथा रचनाओं में व्यक्त दृष्टिकोण संबंधित लेखकों के हैं। संपादक, प्रकाशक एवं मुद्रक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। समस्त प्रकार के विवादों का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

संपादकीय

लोकतंत्र और अराजकता के बीच एक संघर्ष जारी है। यह केवल भारत ही नहीं, अपितु दुनिया के अनेक देशों को अपने जाल में जकड़ चुका है। अरब स्प्रिंग के नाम से उत्तरी अफ्रीका और मध्य-पूर्व देशों में प्रारंभ हुए इस षड़यंत्र को वैश्विक शक्तियों का समर्थन हासिल है। अपने यहां आजादी और मानवाधिकार की दुहाई देने वाले देशों के हाथ विकासशील देशों में चुनी हुई सरकारों को गिराने के खेल में लिप्त दिखते हैं।

भारत एक ऐसा देश है, जहां लोकतंत्र की जड़ें गहरी हैं। सर्वानुमति और सर्वसमावेशी दृष्टिकोण यहां की जीवनशैली का अभिन्न हिस्सा है। अतः यहां चुनी हुई सरकारों को अपदस्थ कर पाना सरल नहीं है। इसके विपरीत जिन देशों में लोकतांत्रिक ढ़ांचा अत्यंत पतली पर्त पर टिका है, वहां उसे कभी भी ढ़हा देना इन शक्तियों के लिए बाएं हाथ का खेल है।

बांग्लादेश का उदाहरण हमारे सामने है, जहां एक लाख से भी कम लोगों की अराजक भीड़ ने पूरे शासन तंत्र को बंधक बना लिया। मजहब के नाम पर न तो आम नागरिक और न ही सेना, इस अराजकता का प्रतिरोध कर सकी और निर्वाचित प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा। शेख हसीना और उनके शासन के गुण-दोषों का विश्लेषण यहां प्रासंगिक नहीं है, किन्तु सेंट मार्टिन द्वीप पर नियंत्रण को लेकर जिस अमेरिकी दबाव का उल्लेख हसीना ने किया है, वह अवश्य भारत के लिए चिन्ता का विषय है।

भारत एक ऐसा देश है, जहां लोकतंत्र की जड़ें गहरी हैं। सर्वानुमति और सर्वसमावेशी दृष्टिकोण यहां की जीवनशैली का अभिन्न हिस्सा है। अतः यहां चुनी हुई सरकारों को अपदस्थ कर पाना सरल नहीं है।

यद्यपि पहले भी इस बात के संकेत मिलते रहे हैं कि भारत के पूर्वी सीमान्त क्षेत्र पर नियंत्रण को लेकर चीन और अमेरिका, दोनों ही सक्रिय हैं। किन्तु किसी समझौते पर आने की प्रतीक्षा करने के स्थान पर किसी देश को अराजकता में धकेल कर बांह मरोड़कर अपनी बात जबरन मनवाने की बेशर्मी और बंगाल की खाड़ी को दो महाशक्तियों द्वारा अपने स्वार्थपूर्ण हितों का अखाड़ा बनाने की कोशिश से भारत ही सबसे अधिक प्रभावित होगा।

अराजकता फैलाने के यह प्रयास गत अनेक वर्षों से भारत में भी दिखाई दे रहे हैं। असंभव मांगों को लेकर हिंसक-अहिंसक प्रदर्शन, छद्म या गलत समाचार, टूल किट, समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा करने के कुत्सित प्रयास, महीनों-महीनों तक राजमार्गों अथवा रेल मार्गों को बंद कर शासन को पंगु बनाने की चेष्टा और सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई करने पर दमन का आरोप लगाकर पुनः आक्रोश पैदा करने के सुनियोजित षड़यंत्र का शिकार सामान्य जनमानस हो रहा है।

इतना ही नहीं, गत लोकसभा चुनाव के दौरान विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों को विदेश से प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता और उन्ही व्यक्तियों एवं संगठनों द्वारा चुनावों को प्रभावित करने के लिए की गई गतिविधियों के बीच प्रथमदृष्टया संबंध स्थापित होता दिखता है। चुनाव में अपेक्षित बदलाव न आ पाने के बाद भी वह लोग और संगठन सक्रिय हैं और निरंतर देश-विघातक मांगें और शब्दों से विषवमन कर रहे हैं। यह स्थिति चिंतनीय है। एक ओर सभी छात्र युवाओं को इन परिस्थितियों से अवगत कराने और दूसरी ओर भारत विरोधी एजेंडे के सफल प्रतिकार की दोहरी चुनौती हमारे सामने है।

हार्दिक शुभकामना सहित

आपका
संपादक

अराजकता के घेरे में 'सोनार बांग्ला'

कट्टरपंथी हिंसा का शिकार बनते अल्पसंख्यक

■ संजय दीक्षित

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हो रही हिंसा, उत्पीड़न एवं अत्याचार के विरोध में देश की राजधानी दिल्ली से लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में धरना-प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बांग्लादेश का आधिकारिक मीडिया अल्पसंख्यकों विशेष रूप से अल्पसंख्यक हिन्दुओं के उत्पीड़न से जुड़ी घटनाओं को अनदेखा कर रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पर अल्पसंख्यक हिन्दुओं के उत्पीड़न से जुड़ी घटनाओं के समाचार देखकर इंसानियत शर्मसार हो रही है। बांग्लादेश में हो रही हिंसक घटनाओं पर भारत के अधिकांश राजनीतिक दल चुप्पी साधे हुए हैं।

बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिन्दुओं के विरुद्ध जारी हिंसा, उत्पीड़न एवं अत्याचार का ताजा घटनाक्रम गत अगस्त माह में अराजकता फैलाकर अवामी लीग सरकार को सत्ता से हटाने के बाद प्रारम्भ हुआ। राजनीतिक रूप से अवामी लीग के विरुद्ध हुए हिंसक आंदोलन एवं अराजकता का घातक प्रभाव अल्पसंख्यक हिन्दुओं को भुगतना पड़ा। बांग्लादेश के लगभग सभी जिलों में हिंसक भीड़ ने अल्पसंख्यक हिन्दुओं का निशाना बनाया। राजधानी ढाका सहित कई जिलों में उनके घरों को लूटकर जलाया गया। मंदिरों और गुरुद्वारों में तोड़फोड़ की गई। तमाम दावों के बाद भी बांग्लादेश

के सभी जिलों में होने वाली हिंसा को रोकने में अंतरिम सरकार असमर्थ सिद्ध हो रही है।

बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक हिन्दुओं को शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग का समर्थक माना जाता है। यही कारण रहा कि अराजकता फैलाकर हुए सत्ता परिवर्तन के बाद अल्पसंख्यक हिन्दुओं को सुनियोजित रूप से निशाना बनाया जा रहा है। सरकारी एवं निजी क्षेत्र में काम करने वाले अल्पसंख्यक हिन्दू कर्मचारियों को जबरन काम से हटाने के साथ ही उनका उत्पीड़न करके मतांतरण के लिए दबाव बनाने में जुटे भारत विरोधी कट्टरपंथी तत्वों पर कानून का कोई अंकुश फिलहाल दिखाई नहीं देता है।

अल्पसंख्यक हिन्दुओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा में भारत विरोधी जमात-ए-इस्लामी सहित अन्य कट्टरपंथी संगठनों की नकारात्मक भूमिका पुनः सामने आई है। जमात-ए-इस्लामी वही कट्टरपंथी संगठन है, जिसने बांग्लादेश की स्वतंत्रता और पाकिस्तान के विखंडन का कड़ा विरोध करते हुए 1971 में बांग्लादेश के राष्ट्रवादियों और बुद्धिजीवियों की सामूहिक हत्या में पाकिस्तानी सेना का साथ दिया था। पूर्वी पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश बनने और फिर बांग्लादेश के पूर्ण इस्लामीकरण के एजेंडे को पूरा करने के लिए लाखों हिन्दुओं की हत्या, उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण की अनेकों घटनाओं में जमात-ए-इस्लामी की संलिप्तता कई बार उजागर हो चुकी है। बांग्लादेश में अराजकता फैलाकर अंतरिम सरकार का गठन होने के बाद कट्टरपंथी तत्वों के दबाव में गत 28 अगस्त को जमात-ए-इस्लामी पर लगे प्रतिबन्ध को हटा लिया गया।

दलित वर्ग के हैं अधिकांश हिन्दू

बांग्लादेश में भारत विरोधी कट्टरपंथियों के शिकार बन रहे अल्पसंख्यक हिन्दुओं में अधिकांश दलित वर्ग के हैं। दशकों से अल्पसंख्यक हिन्दू हिंसा, उत्पीड़न एवं अत्याचार का शिकार बन रहे हैं। जानकर हैरत होगी कि 1947 में भारत विभाजन के साथ पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जिस प्रान्त का जन्म हुआ था, उस भू-क्षेत्र में 1951 की जनगणना के अनुसार हिन्दू जनसंख्या 22.05 प्रतिशत थी। इनमें से अधिकांश दलित वर्ग के थे।

1946 में हुए हिन्दू-मुस्लिम दंगों के बाद कथित "दलित-मुस्लिम सामाजिक एकता" के नाम पर जो दलित हिन्दू बांग्लादेश गए, उन्हें बाद में अपने निर्णय पर पछताना पड़ा। तत्कालीन समय में दलित नेता जोगेंद्र नाथ मंडल कथित दलित-मुस्लिम एकता के नाम पर नेता मोहम्मद अली जिन्ना की साजिश का शिकार बने, जिन्हें अपनी जान बचाने के लिए बाद में पाकिस्तान से भागकर भारत आना पड़ा।

पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश बनने तक और फिर बांग्लादेश के इस्लामिक समाज ने अल्पसंख्यक हिन्दुओं को कभी भी स्वीकार नहीं किया। इस्लामिक शासन एवं इस्लामिक सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने का एजेंडा लेकर चल रहे भारत विरोधी कट्टरपंथियों द्वारा हिंसा फैलाकर कराए जाने वाले जबरन धर्मांतरण, शोषण, उत्पीड़न के कारण बांग्लादेश की जनसंख्या में हिन्दुओं की हिस्सेदारी वर्तमान में लगभग 7.95 प्रतिशत रह गई है। भारत में सत्ता हासिल करने के लिए कथित दलित-हिन्दू सामाजिक एकता की पैरवी करने वाले राजनीतिक दलों, संगठनों एवं नेताओं में से कोई भी बांग्लादेश में उत्पीड़ित हो रहे दलित हिन्दुओं के मुद्दे पर खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है।

अराजकता फैलाकर गिराई गई हसीना सरकार

लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार में प्रधानमंत्री पद संभालने वाली शेख हसीना बांग्लादेश के स्वतंत्र इतिहास के 53 वर्षों में से 28 वर्ष सत्ता में रही हैं। अवामी लीग की नेता के रूप में इसी वर्ष चौथी बार प्रधानमंत्री पद संभालने वाली शेख हसीना की छवि एक ऐसे नेता की थी, जो बांग्लादेश के समग्र विकास के लिए काम कर रही थी। अपने कार्यकाल में भारत विरोधी कट्टरपंथी तत्वों पर अंकुश लगाने वाले वाली शेख हसीना को अराजकता फैलाकर प्रधानमंत्री पद से जबरन इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया गया। उन्हें अपनी जान बचाने के लिए गत 5 अगस्त को भागकर दिल्ली आना पड़ा।

अराजकता फ़ैलाकर शेख हसीना से सत्ता छीनने के लिए उनके राजनीतिक विरोधियों ने कट्टरपंथी शक्तियों के साथ मिलकर आरक्षण की उस नीति को हथियार बनाया, जिसके अंतर्गत बांग्लादेश में स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को सरकारी नौकरियों में तीस प्रतिशत आरक्षण दिया गया था। सरकारी क्षेत्र में आरक्षण व्यवस्था को लेकर बांग्लादेश में वर्षों से विवाद की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन चौथी बार लोकतान्त्रिक ढंग से चुनाव जीतने के बाद आरक्षण विरोध के नाम पर जुटाई गई कट्टरपंथियों की भीड़ ने अराजकता फैलाकर शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर दिया।

अंतरिम सरकार का गठन

कथित आरक्षण आंदोलन की आड़ में शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करने के बाद सेना ने बांग्लादेश की कमान संभाल ली। अराजकता फैलाने वाले कट्टरपंथी नेताओं एवं संगठनों की मांग पर सेना द्वारा गठित अंतरिम सरकार के मुखिया के रूप में मुहम्मद यूनुस को सामने लाया गया। मुहम्मद यूनुस एक अर्थशास्त्री हैं, जिन्हें लघु ऋण क्षेत्र में काम करने के लिए 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। बांग्लादेश में श्रम कानून का उल्लंघन, भ्रष्टाचार, धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग), धोखाधड़ी जैसे गंभीर मामलों में संदिग्ध भूमिका पाए जाने के बाद मुहम्मद यूनुस को जनवरी' 2024 में न्यायालय ने छह माह की कैद की सजा सुनाई, पर अपील लंबित रहने तक न्यायालय ने उन्हें ज़मानत दे दी थी। अराजकतापूर्ण ढंग से हुए सत्ता परिवर्तन के बाद गत 7 अगस्त को उनकी सज़ा को रद्द करके बरी कर दिया गया। इसी तरह एक अन्य मामले में भी उन्हें दोषमुक्त किया गया।

भारत विरोधियों के हाथ में सत्ता

मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार की सहायता के लिए बनाई गई सलाहकारों की सोलह सदस्यीय परिषद में कथित छात्र आंदोलन के दो प्रमुख नेताओं के साथ ही कई अन्य कट्टरपंथी नेताओं को शामिल किया गया है। अराजकतापूर्ण ढंग से हुए सत्ता परिवर्तन को "दूसरी बार मिली आजादी" की संज्ञा देने वाले मोहम्मद यूनुस का समर्थन, कट्टरपंथी तत्वों के साथ वह सभी देशी-विदेशी शक्तियां कर रही हैं, जो लंबे समय से हसीना सरकार को हटाने के लिए प्रयासरत थी। अंतरिम सरकार का गठन होने के बाद अराजक भीड़ के दबाव में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित कई अन्य न्यायाधीशों एवं विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोगों को इस्तीफ़ा देने के लिए बाध्य किया गया। सत्ता पर कब्ज़ा करने के बाद कट्टरपंथी भीड़ के दबाव में जेल में आतंकी तत्वों एवं सजायाफ्ता अपराधियों को रिहा करने के साथ ही भारत विरोधी संगठनों पर लगे प्रतिबंधों का हटाया जा रहा है।

अराजकता की सुनियोजित साजिश

अपने लंबे शासन काल के दौरान शेख हसीना ने बांग्लादेश को स्थिरता प्रदान करने के साथ विकास की दिशा में आगे बढ़ाने का काम किया। उन्होंने पूर्ण रूप से इस्लामिक शासन की पैरवी करने वाले कट्टरपंथी राजनीतिक दलों, संगठनों एवं समूहों पर नियंत्रण बनाए रखा, जिसके कारण विपक्षी दलों ने अबकी बार आम चुनाव का बहिष्कार किया था। लगातार चौथी बार सत्ता संभालने वाली हसीना सरकार के विरुद्ध आरक्षण विरोध को हथियार बनाकर छात्रों को सुनियोजित रूप से इस तरह भड़काया गया कि वह आरक्षण की आड़ में सरकार विरोधी आंदोलन का हिस्सा बन गए। गत जुलाई माह से छात्रों के नाम पर प्रारंभ हुए विरोध-प्रदर्शन को भड़काने में जमात-ए-इस्लामी (बांग्लादेश) और उसकी छात्र शाखा छात्र शिबिर की सक्रिय भूमिका रही।

बांग्लादेश में पूर्ण इस्लामिक सत्ता स्थापित करने के एजेंडे को लेकर एकजुट हुए कट्टरपंथी तत्वों, संगठनों, राजनीतिक दलों एवं भारत विरोध के लिए हर पल अवसर की तलाश में रहने वाले तथाकथित धर्मनिरपेक्ष वामपंथियों ने शेख हसीना को तानाशाह बताते हुए अराजकता को बढ़ावा दिया। परिणाम

कट्टरपंथियों की गतिविधियों को उजागर किया सीडीपीएचआर की रिपोर्ट ने

बांग्लादेश में अराजकता फैला कर हसीना सरकार को सत्ता से हटाए जाने और अल्पसंख्यक हिन्दुओं पर हुए हिंसक हमलों को लेकर सेंटर फॉर डेमोक्रेसी, प्लूरलिज्म एंड ह्यूमन राइट्स (सीडीपीएचआर) नामक संगठन ने एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में हसीना सरकार को हटाए जाने के बाद अल्पसंख्यक हिन्दुओं पर हुए हमलों के साथ ही भारत विरोधी कट्टरपंथियों की गतिविधियों को उजागर किया गया है। संगठन की अध्यक्ष डा. प्रेरणा मल्होत्रा ने बताया कि बांग्लादेश में गत 5 अगस्त को अराजकता और हिंसा फ़ैलाने वाली कट्टरपंथी भीड़ ने 27 जिलों में अल्पसंख्यकों के घरों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। बाद में यह हिंसा 52 जिलों तक फैल गई और अल्पसंख्यक हिन्दुओं के विरुद्ध हुए हमलों की संख्या बढ़कर 205 हो गई।

संगठन ने राजधानी दिल्ली में जारी की गई अपनी रिपोर्ट में गत 5 अगस्त से 9 अगस्त के मध्य हुई 110 घटनाओं की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि अल्पसंख्यक हिन्दुओं को सुनियोजित रूप से निशाना बनाया गया। उनके घरों, दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, मंदिरों को लूटकर तोड़ा गया और आग लगा दी गई। कई जगहों पर अल्पसंख्यक हिन्दुओं की हत्या कर दी गई और महिलाओं का उत्पीड़न किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि बांग्लादेश में भयपूर्ण वातावरण में रह रहे हिन्दू अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव बढ़ता जा रहा है। उनकी स्थिति और ख़राब होती जा रही है।

92 पृष्ठ की रिपोर्ट में अराजकता फैलाकर किए गए सत्ता परिवर्तन, अमेरिका की संदिग्ध भूमिका, भारत विरोधी कट्टरपंथियों सहित कई मुद्दों की विस्तार से चर्चा की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बांग्लादेश में

सत्ता हथियाने के लिए कट्टरपंथियों ने उसी रणनीति का प्रयोग किया, जैसी रणनीति मध्य-पूर्व, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान में अपनाई गई थी। कट्टरपंथी तत्वों एवं संगठनों की डोर जमाते-इस्लामी संगठन के हाथ में है, जिसे भारत विरोधी गतिविधियों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। लेकिन बांग्लादेश में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद लगा हुआ प्रतिबंध हटा दिया गया है।

रिपोर्ट जारी होने के अवसर पर पूर्व सांसद एवं विख्यात पत्रकार स्वप्न दासगुप्ता ने कहा कि हसीना सरकार को सत्ता से हटाने के बाद बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर्रहमान की प्रतिमाओं के साथ ही उनसे जुड़े स्थानों एवं संग्रहालय को नष्ट कर दिया गया। वहां अल्पसंख्यक हिन्दुओं को दशकों से निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ी आवश्यकता बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक हिन्दुओं में यह भरोसा पैदा करने की है कि भारत उनके साथ है और जो अल्पसंख्यक हिन्दू वहां से भारत आ रहे हैं, उनका स्वागत किया जाना चाहिए।

सीडीपीएचआर द्वारा राजधानी दिल्ली में गत 4 सितंबर को रिपोर्ट जारी किए जाने के अवसर पर लेखक दीप हलदर एवं अभिजीत मजूमदार सम्माननीय अतिथि के रूप में उपस्थित थे। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

पूरे बांग्लादेश में हिंसा, आगजनी और हत्याओं के रूप में सामने आया। कट्टरपंथ और भारत विरोध से प्रेरित हिंसक और अनियंत्रित भीड़ ने आंदोलन की आड़ में अवामी लीग के कई नेताओं की हत्या करने के साथ ही सैकड़ों नेताओं एवं कार्यकताओं के घरों-प्रतिष्ठानों को लूटकर आग के हवाले कर दिया। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले शेख मुजीबुर्रहमान की प्रतिमाओं को नष्ट करने के साथ ही उनके नाम पर बने संग्रहालय को जला दिया गया। अपनी स्वतंत्रता की निशानियों को मिटाने के साथ ही कट्टरपंथियों की भीड़ ने भारत-बांग्लादेश मैत्री एवं सकारात्मक संबंधों को दर्शाने वाले प्रतीकों एवं साझी विरासत को भी निशाना बनाया।

अमेरिका-चीन की संदिग्ध भूमिका

बांग्लादेश में अराजकता फैलाकर लोकतंत्र और लोकतांत्रिक सरकार को गिराए जाने में अमेरिका की संदिग्ध भूमिका कठघरे में है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी अमेरिका पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। शेख हसीना के अनुसार उन्होंने अमेरिका को बंगाल की खाड़ी में स्थित सेंट मार्टिन द्वीप पर सैन्य अड्डा बनाने की अनुमति देने से इंकार कर दिया था। इसीलिए अमेरिका ने उनकी सरकार को निशाना बनाया है।

जानकारी हो कि सेंट मार्टिन द्वीप बांग्लादेश का हिस्सा है और बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पूर्वी हिस्से में तीन किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है। बंगाल की खाड़ी और म्यांमार के साथ समुद्री सीमा जुड़ने के कारण इस द्वीप पर अमेरिका और चीन की निगाह लंबे समय से लगी हुई है। दोनों ही देश यहां पर अपना कब्ज़ा चाहते हैं। अमेरिका की रूचि सेंट मार्टिन द्वीप में इसलिए भी है क्योंकि हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति ने अमेरिका के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। चीन से निपटने के लिए अमेरिका लगातार सेंट मार्टिन द्वीप पर अपना कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है।

सुरक्षा विश्लेषक बताते हैं कि अमेरिका को जवाब देने के लिए चीन भी सक्रिय है। चीन रणनीतिक रूप से बंगाल की खाड़ी में अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। वह पिछले कई वर्षों से कोशिश करता आ रहा है कि बांग्लादेश की सरकार उसके हितों के अनुरूप काम करे। इस दौरान बांग्लादेश में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए चीन ने कई प्रयास किए। लेकिन जैसी उम्मीद चीन को थी, वैसी सफलता उसे नहीं मिली। हसीना सरकार ने हर स्तर पर अमेरिका और चीन के दबाव को अस्वीकार कर दिया।

सक्रिय है पाकिस्तान भी

बांग्लादेश में पाकिस्तान की सक्रियता नई नहीं है। बांग्लादेश का गठन होने के बाद से ही पाकिस्तान के कट्टर राजनीतिक दल, इस्लामिक संगठनों के साथ ही ख़ुफ़िया एजेंसी इंटर-सर्विसेस इंटेलिजेंस (आईएसआई) दशकों से अपनी भारत विरोधी गतिविधियों के लिए बांग्लादेश का इस्तेमाल करती आ रही है। उत्तर-पूर्वी राज्यों में आतंकवाद फ़ैलाने के साथ ही भारतीय सीमा क्षेत्र के भू-भाग में अवैध घुसपैठ के लिए सक्रिय आईएसआई के तंत्र पर अंकुश लगाने का काम हसीना सरकार ने किया था। खुफिया एजेंसी आईएसआई की गतिविधियों पर लगाए गए अंकुश से आईएसआई पोषित भारत विरोधी कट्टरपंथी वर्ग एवं संगठन लंबे समय से कुपित और हताश थे। हताश कट्टरपंथियों के साथ मिलकर आईएसआई भी जबरन सत्ता परिवर्तन के खेल में पर्दे की पीछे से पूरी तरह सक्रिय रही। अल्पसंख्यक हिन्दुओं पर होने वाले हमले और उत्पीड़न की घटनाओं में भी आईएसआई पोषित तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है।

भारत की सतर्क दृष्टि

किसी लोकतांत्रिक देश की लोकतांत्रिक सरकार को अराजकता फैलाकर गिराना और फिर अस्थिरता का लाभ अपने हितों के लिए करने की रणनीति नई नहीं है। अमेरिका सहित कई पश्चिमी देशों के साथ यह खेल चीन भी वर्षों से खेलता आ रहा है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, मालदीव के बाद ऐसा ही खेल बांग्लादेश में खेला गया है। कमोबेश इन सभी देशों में सुनियोजित रूप से पहले

लोकतांत्रिक सरकार को जनविरोधी और तानाशाह सरकार बताकर जनता को उकसाया गया। उसके बाद जनता की भीड़ को सड़क पर लाकर हिंसक धरना-प्रदर्शन करके लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख पर इस्तीफ़ा देने का दबाव बनाकर सत्ता का अपहरण किया गया। यही बांग्लादेश में भी हुआ।

पड़ोस में स्थित बांग्लादेश पर भारत की सतर्क दृष्टि लगी हुई है। पाकिस्तान, चीन के बाद रणनीतिक, सामरिक एवं सुरक्षा की दृष्टि से अब बांग्लादेश भी नई चिंताओं का कारण बनता जा रहा है। अंतरिम सरकार में शामिल नेताओं के बयानों में भारत विरोध की मानसिकता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। अल्पसंख्यक हिन्दुओं के विरुद्ध हो रही हिंसा को लेकर मोदी सरकार ने अपनी चिंता सार्वजनिक रूप से जाहिर करते हुए अंतरिम सरकार को ठोस कदम उठाने का सन्देश भी दिया है। देखना यह होगा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार उन अलगाववादी, कट्टरपंथी एवं भारत विरोधी तत्वों से किस प्रकार निपटेगी, जो भारत विरोध और बांग्लादेश के पूर्ण इस्लामीकरण के एजेंडे पर काम करते हुए हिन्दू अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं। ■

। प्रतिक्रिया ।

बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिन्दुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे सरकार : अभाविप

बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिन्दुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने केंद्र सरकार, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। बांग्लादेश की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते अभाविप ने कहा कि मजहबी कट्टरपंथी शक्तियों ने पूरे बांग्लादेश को अराजकता तथा हिंसा में झोंक दिया है। बांग्लादेश में जिस प्रकार से लगातार हत्याओं सहित वीभत्स कृत्य की घटनाएं सामने आ रही हैं, वह चिंताजनक हैं और इससे संपूर्ण मानवता के लिए गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। बांग्लादेश में जो घटनाक्रम हुआ, उसमें नकारात्मक अंतरराष्ट्रीय शक्तियों ने भी हिंसक, अराजक, अमानवीय तथा मजहबी कट्टरपंथी तत्वों को दिशा दिखाई है।

बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिन्दुओं के विरुद्ध हो रहे अत्याचार के विरोध में राजधानी दिल्ली स्थित जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय की अभाविप इकाई ने मार्च का आयोजन किया। मार्च में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिन्दुओं के विरुद्ध हो रही हिंसा की कड़ी निंदा की। गत 9 अगस्त को आयोजित मार्च में अभाविप जेएनयू इकाई के अध्यक्ष राजेश्वर कांत दुबे ने कहा कि बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध सभी को मिलकर खड़ा होना चाहिए। पीड़ित अल्पसंख्यक हिन्दुओं के जान-माल की सुरक्षा के साथ ही उन्हें न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए।

अभाविप जेएनयू इकाई मंत्री शिखा स्वराज ने भी सभी छात्र-छात्राओं से अपील करते हुए कहा कि वह भी इस मुद्दे पर बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाएं ताकि अल्पसंख्यक हिन्दुओं के विरुद्ध हो रही हिंसा को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के अलग-अलग हिस्सों से अल्पसंख्यक हिन्दुओं के मकान, व्यापारिक स्थल, पूजास्थलों पर लगातार हमले के समाचार प्राप्त हो रहे हैं। अभाविप मांग करती है कि केंद्र सरकार तथा अन्तरराष्ट्रीय संस्थाएं, बांग्लादेश में शांति स्थापना के लिए शीघ्र उचित हस्तक्षेप करें। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

FROM DIRECT ACTION DAY AUGUST 1946 TO QUOTA PROTEST 2024

ANNIHILATION OF HINDUS IN BANGLADESH

Amrita Shilpi

The Hindu community in Bangladesh has faced severe atrocities over the decades, starting from the Direct Action Day in 1946 and continuing through various periods of violence, including the Noakhali genocide in 1946, the 1971 Bangladesh Liberation War, and recurrent pogroms such as in 1992 and 2024. These events have resulted in massacres, rapes, abductions and the systematic destruction of Hindu properties, leading to a significant decline in the Hindu population.

The Hindu population has undergone a steady attrition over the years, from 28% in 1940 to 8.96% in 2011, with especially two periods of sharp decline—the first around the time of partition and the second during the 1971 Bangladesh War that resulted in the liberation of Bangladesh. Over the past 50 years, the total population of the country has more than doubled, but not in the case of Hindus. The number of Hindu persons in the country had dropped by around 7.5 million (75 lakh). The number of Buddhists, Christian and persons of other religions has remained more or less constant.

The history of atrocities against Hindus in Bangladesh underscores a pattern of systemic violence and persecution spanning decades. This persecution of Hindus highlights their on-going struggle for safety and rights from the very first day.

1946 DIRECT ACTION PLAN

The Muslim League Council proclaimed August 16, 1946 as 'Direct Action Day' in order to accentuate their demand for a separate Muslim homeland after the British left the Indian subcontinent. Their main aim was to attain a different country with a Muslim majority. Muslims chose August 16, 1946 as the day to accomplish their mission simply because the Battle of Badr occurred on this day and it resulted in the first decisive victory of Islam over the heathens and the subsequent conquest of Mecca.

The All-India Muslim League decided to take a "direct action" using violence to intimidate Hindus and their leadership for a separate Muslim homel and after the British exit from India. SN Usman, the Mayor of Calcutta and the Secretary of the Calcutta Muslim League circulated a leaflet in Bangla which read "Kafer! Toderdhongsheraarderinei!

Sarbikhotyakandoghotbe!" ("Infidels! Your end is not far off! There will be a massacre!").

An Additional Judge of Alipore Court was killed while trying to save a little boy who was fleeing for his life from the goondahs. Until midmorning of this day, that is the 17th there was no sign of any policemen anywhere. A mob of violent Islamists attacked on Victoria college. All girls were raped in classroom, then killed and hung naked on windows. Hindu girls' naked bodies were hung from hooks at Raja Bazar beef shops. Large number of the participants was reported to have been armed with iron bars and lathis.

The bestiality of Razakars affected Hindus of Kolkata across sections, castes, class, professions. In another shocking incident in Metiaburuz, around seven hundred Bihari and Odiya labourers were butchered by a Muslim mob which was led by local communist party leader Sayed Abdulla Farooqui. On 17 August, Farooqui, the President of Garden

Reach Textile Workers' Union, along with Elian Mistry, a hardline Muslim League hooligan, led a huge armed mob into the mill compound of Kesoram Cotton Mills in the Lichubagan area. Gopal 'Patha' saved Hindus from sure-shot annihilation by the Islamist terrorists of Suhrawardy and Jinnah during Direct Action in 1946.

1946 NOAKHALI GENOCIDE

Noakhali Genocide were a series of organised massacres, rapes and abductions, combined with looting and arson of Hindu properties, perpetrated by the Muslim community in the districts of Noakhali in the Chittagong Division of Bengal (now in Bangladesh) in October–November 1946, a year before India's independence from British rule. It affected the areas under the Ramganj, Begumganj, Raipur, Lakshmipur, Chhagalnaiya and Sandwip police stations in Noakhali district and the areas under the Hajiganj, Faridganj, Chandpur, Laksham and Chauddagram police stations in Tipperah district, a total area of more than 2,000 square miles.

The massacre of the Hindu population started on October 10, on the day of Kojagari Lakshmi Puja and continued unabated for about a week. Around 50,000 Hindus remained marooned in the affected areas under the strict surveillance of the Muslims, where the administration had no say. In some areas, Hindus had to obtain permits from the Muslim leaders in order to travel outside their villages.

THE PARTITION OF 1947

The Partition of India after the British left, bifurcated the land into three, with one being Bharat, East Pakistan and West Pakistan. Although the populations of both zones were almost equal, the political concentration and the decision-making bodies were concentrated in west Pakistan only. When the partition of India and Pakistan was in papers only, a request for an independent and united Bengal was mooted by the then-Prime Minister of Bengal in British India (1946-1947). However, his demands were never met and partition was done as per Mountbatten's plan.

The authorities of West Pakistan viewed the Bengali Muslims in the East as "too 'Bengali'" and their application of Islam as "inferior and impure", believing this made the Bengalis unreliable "co-religionists". And the Bengali Hindus were always under their target. The authorities at the west started assimilating the Bengalis culturally. In March 1948, The founder of Pakistan, Jinnah declared in a civic reception in Dhaka that "Urdu and only Urdu will remain as the state language of Pakistan". The students of Dhaka University instantly protested this declaration in front of Jinnah which led to army invitation in East Pakistan.

Army units entered villages asking where Hindus live; it was "common pattern" to kill Hindu males. Hindus were identified because they were not circumcised. There were barely any areas where no Hindu was killed. Sometimes the military also massacred Hindu women.

1971 GENOCIDE

'71's genocide' was the ethnic cleansing of Bengalis, especially Bengali Hindus, residing in East Pakistan (now Bangladesh) during the Bangladesh Liberation War, perpetrated by the Pakistan Armed Forces and the Razakars. In the eyes of the Pakistani military, Hindu, Bengali, and Indian identities were one and the same. Although Hindus were a special target of the Pakistan military, Bengali Muslim, Christian, Buddhist, and other religious groups were also significantly affected. By the end of the first month in March 1971, 1.5 million Bengalis were displaced. By November 1971, 10 million Bengalis, the majority of whom were Hindu, had fled to India. On March 25, 1971, the Pakistan military began a 10-month campaign of genocide

against the ethnic Bengali and Hindu religious communities in East Pakistan, a clear example of the facets of genocide as defined the United Nations Genocide Convention. This spurred the 10-month Bangladesh Liberation War and later the 13 day Indo-Pakistan war. Both ended on December 16, 1971 with the surrender of Pakistan.

Bangladeshi journalist and policy analyst Anushay Hossain asserts, "many experts put that number closer to 400,000 women and girls who were raped, mass-raped, imprisoned for months in notorious rape camps."

Pakistan's imams declared Bengali Hindu women to be "war booty"; and Pakistani fatwa were issued legitimizing Bengali Hindu women as spoils of war. Women who were targeted often died in Pakistani captivity or committed suicide, while others fled to India. Countless women were subjected to looting and rape by the Pakistani army. Hindu massacres were carried out with alarming frequency, one of which was the infamous Burunga massacre. On May 26, 1971, the Pakistani army mercilessly murdered 94 Hindus at Burunga High School. This appalling incident is just one among numerous horrific massacres inflicted upon the Hindu population in Bangladesh.

Pakistani army personnel killed thousands of people including academics, students, and sleeping rickshaw pullers at close ranges. The eminent academicians killed on the fateful night included venerable GC Dev and the scholar Jyotirmoy Guhathakurta. As many as 3 million people were killed, with more than 10 million forced to take refuge in the neighbouring country, India.

1992 DEMOLITION OF DISPUTED STRUCTURE LED TO TEMPLE DESTRUCTION IN BANGLADESH

1992 Bangladesh pogroms was a series of violence against the Bengali Hindus by Islamists against the demolition of disputed structure (Babri Masjid), driven out of hate and revenge mindset continuing from almost 1947. The incidents of violence began in December 1992 and continued till March 1993.

On 7 December, the Dhakeshwari temple was attacked. The Bholanath Giri Ashram in Dhaka was attacked and looted. Hindu owned jewellery shops were looted in old Dhaka. Hindu houses in Rayerbazar were set on fire. (Taslima Nasreen has also mentioned in her novel 'Lajja' how the Dhakeshwari temple was attacked in 1992. The main temple was burnt.) The SAARC Quadrangular cricket tournament was affected due to the riots. On 7 December, 5,000 Muslims armed with iron rods and bamboo sticks tried to storm into the Dhaka National Stadium, where the match between Bangladesh and India was under progress. The police fired tear gas and rubber bullets to stave off the attackers, but the match was abandoned after 8.1 overs. The organizers rescheduled the match on 10 December and the final between India A and Pakistan A on 11 December, but both of them were eventually cancelled.

On 8 December, Hindus were attacked in KutubdiaUpazila in Cox's Bazar District. Muslims attacked 14 Hindu temples, eight of them were burnt and six damaged. 51 Hindu houses in Ali Akbar Dale and another 30 in Choufaldandi. In Sylhet, one house was burnt in the heart of the town and 10 other temples were torched. In Chittagong District, the Fatikchari and Mireswari villages were burnt completely. Five Hindu temples including Panchanan Dham and Tulsi Dham were attacked and damaged.

By the time the situation cooled off a total of 10 people were reportedly killed, and several Hindu temples and homes were destroyed.In 1992, Jamaat-e-Islami, an ally of the ruling party BNP (Bangladesh Nationalist Party), was itself involved in the violence.

Notably, in October 1990, 26 months before the demolition, a rumour was spread

by the media of Bangladesh that the disputed Babri structure had been demolished in India. Soon after then, violence erupted in different parts of Bangladesh, leading to the demolition of over 3,500 temples and sexual brutalities against over 2,400 Hindu women.

Properties belonging to Hindus were being set on fire. The 'Human Rights Congress for Bangladesh Minorities' (HRCBM) said in its report that all this happened in front of the police administration. The report stated that in 1989-90 alone, more than 1000 women were raped, hundreds of temples were demolished and houses of Hindu minorities were looted and set on fire.

CONTINUOUS VIOLENCE AGAINST HINDU COMMUNITY IN BANGLADESH

Ahead of the Bangladesh elections, the Hindu community was facing the wrath of political violence. Several Hindu families were forced to vacate their houses in Shailkupaupazila in the Khulna division of Bangladesh and sell them at giveaway prices to avoid religious persecution. As per a report by Kalbela News, the minority community was facing threats from Islamists and hence many Hindu families are migrating to other parts of the country. On an average more than 1000 temple and hindus homes were attacked, 1000's of sexual assaults on Hindu women were reported in the past few years.In recent violence 2024 around 500 people have died and most of them are hindus in violent protests rooted in quota protests. Anti-government protestors marched to Dhaka and stormed into the PM's palace following a weekend of violence left dozens of people dead as the military imposed a curfew for an indefinite period and authorities cut off internet access in an attempt to stem the unrest. ■

I राजस्थान I

अजमेर बलात्कार कांड में छह अभियुक्तों को आजीवन कारावास

अजमेर में 32 वर्ष पहले हुए यौन शोषण एवं उत्पीड़न के मामले में शामिल छह अभियुक्तों को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) न्यायालय ने आजीवन कारावास और पांच-पांच लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध 23 जून 2001 को आरोपपत्र दाखिल किया गया था, जिस पर इसी वर्ष सुनवाई पूरी हुई थी। गत 20 अगस्त को अजमेर के पोक्सो न्यायालय द्वारा जिन अभियुक्तों को सजा सुनाई गई, उनमें नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, सोहेल गनी और सईद जमीर हुसैन शामिल हैं। एक अन्य फरार आरोपी के विरुद्ध केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है।

1992 में अजमेर सेक्स कांड के नाम से कुख्यात हुए मामले में सौ अधिक लड़कियों को बलात्कार का शिकार बनाया गया, जिनमें कई नाबालिग थीं। अभियुक्तों ने सुनियोजित ढंग से पीड़ित लड़कियों की नग्न तस्वीरें निकल कर उन्हें ब्लैकमेल किया, जिसके कारण कई लड़कियां आत्महत्या करने के लिए विवश हो गई। सभ्रांत परिवारों की लड़कियों के साथ हुए यौन शोषण, बलात्कार एवं ब्लैकमेल करने का मामला सामने आने के बाद राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरोसिंह शेखावत ने सीआईडी-सीबी को जांच सौंप दी थी।

अजमेर कांड में जिन 18 आरोपियों के नाम शामिल थे, उनमें तत्कालीन युवा कांग्रेस के अध्यक्ष फारूख चिश्ती, उपाध्यक्ष नफीस चिश्ती, महामंत्री नवर चिश्ती का नाम भी था। इस मामले में नवंबर 1992 में आठ अभियुक्तों के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल किया गया था, जबकि अन्य चार अभियुक्तों के विरुद्ध अलग-अलग आरोपपत्र दाखिल किए गए। वर्षों तक न्यायायिक कार्यवाई के दौरान कई अभियुक्त फरार भी हो गए थे, जिन्हें बाद में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अब इस मामले में पोक्सो न्यायालय ने छह अभियुक्तों को सजा सुनाई है। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

‘संडे फॉर बीएचयू’ अभियान के 50 रविवार पूरे

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) की काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) विकासार्थ विद्यार्थी (एसएफडी) इकाई द्वारा चलाए जा रहे संडे फॉर बीएचयू अभियान के लगातार 50 रविवार पूरे होने के मौके पर क्लाइमेट स्मार्ट बीएचयू विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। साथ ही रविवार को 50वें अभियान के अन्तर्गत एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त परिसर हेतु अभियान चलाया गया।

संडे फॉर बीएचयू अभियान के 50 रविवार पूरे होने पर आयोजित संगोष्ठी में अभियान की यात्रा पर प्रकाश डालते हुए अभाविप काशी हिंदू विश्वविद्यालय इकाई के मंत्री भाष्करादित्य त्रिपाठी ने कहा कि विश्वविद्यालय को एकल उपयोगी प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए गत वर्ष 3 सितंबर से आरम्भ हुए अभियान ने अपने 50 रविवार पूरे कर लिए हैं। इस अवधि में विश्वविद्यालय परिसर की ऐसी कोई सड़क नहीं है, जिसे स्वच्छ करने का कार्य नहीं किया गया होगा। अभियान के कारण बड़ी संख्या में लोग जागरूक हुए हैं और इसका प्रभाव परिसर में भी दिखाई देने लगा है। परिसर को हरा-भरा और सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने में विश्वविद्यालय के छात्र, शिक्षक, कर्मचारी एवं अंतःवासियों को आगे आकर अभियान में अपनी भूमिका का निर्वहन करना होगा।

विकासार्थ विद्यार्थी के राष्ट्रीय प्रमुख राहुल गौड़ ने बताया कि अभाविप एक मात्र ऐसा छात्र संगठन है, जिसकी निगाह शैक्षिक समस्याओं के समाधान के साथ ही परिसर के वातावरण और पर्यावरण से संबंधित समस्याओं पर भी बनी हुई है। इसलिए अभाविप की बीएचयू इकाई परिसर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए कार्य कर रही है और 50 रविवार भी पूरे कर चुकी है। अपनी इस यात्रा के अगले पड़ाव में एसएफडी जल, जंगल, जमीन, जानवर, जन को ध्यान में रखते हुए क्लाइमेट स्मार्ट बीएचयू पर भी काम करेगी, जिसके व्यापक और सकारात्मक परिणाम भविष्य में दिखाई देंगे।

कार्यक्रम के विशिष्ट वक्ता प्रो. सत्यनारायण संखवार ने भी अभाविप के सार्थक अभियान की प्रशंसा करते हुए अभियान में सहयोग देने का आह्वान किया। संगोष्ठी की

अध्यक्षता करने वाले वाणिज्य संकाय के डीन प्रो. एच. के. सिंह ने जनसमूह से इस अभियान से जुड़ने के लिए आग्रह किया। संगोष्ठी में आए छात्रों का धन्यवाद देते हुए बीएचयू इकाई के अध्यक्ष प्रशांत राय ने कहा कि सभी को मिलकर परिसर को स्वच्छ, सुंदर, प्लास्टिक मुक्त बनाना होगा। इस अवसर पर एसएफडी की राष्ट्रीय सह संयोजक पायल राय, काशी प्रांत संगठन मंत्री अभिलाष मिश्र, प्रो. फतेह बहादुर सिंह सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित थे।

जानकारी हो कि संडे फॉर बीएचयू अभियान के अंतर्गत प्रत्येक रविवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में अभाविप द्वारा प्लास्टिक मुक्त बीएचयू अभियान चलाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण और प्लास्टिक मुक्त विश्वविद्यालय परिसर कार्यक्रम में अब तक विश्वविद्यालय के पांच सौ से अधिक कर्मचारी, शिक्षक और स्वयंसेवकों द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक को एकत्रित करके स्वच्छता अभियान चलाया जा चुका है। अभियान का आरंभ 3 सितंबर 2023 को हुआ था। समाज में पर्यावरण के प्रति जागरूकता एवं पर्यावरण के संरक्षण के उद्देश्य छात्रों को जोड़कर चलाए जा रहे अभियान को देखते हुए कई अन्य विश्वविद्यालयों तथा संगठनों ने भी अपने परिसर एवं क्षेत्रों में संडे फॉर सोसाइटी के नाम से अभियान आरंभ किए हैं। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

दत्ताजी डिडोलकर जन्मशती वर्ष का समापन

परिस्थितियों के कारण नहीं बदलनी चाहिए संगठन की दिशा : डा. भागवत

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के संस्थापन काल के अग्रणी कार्यकर्ता दत्ताजी डिडोलकर जन्मशती वर्ष के समापन अवसर पर आयोजित समारोह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डा. मोहन भागवत ने अभाविप कार्यकर्ताओं से दत्ताजी द्वारा दिखाई दिशा पर चलने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अनुकूल हो या प्रतिकूल, हर परिस्थिति में कार्यकर्ताओं की दिशा सही रहनी चाहिए। समाज की परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन संगठन की दिशा नहीं बदलनी चाहिए।

नागपुर स्थित कविवर्य सुरेश भट सभागृह में गत 7 अगस्त को आयोजित समारोह में सरसंघचालक डा. भागवत ने कहा कि दत्ताजी ने विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल बनाकर कार्यकर्ताओं की एक सेना तैयार की, जो दृढ़ संकल्प का एक महान ध्रुव था। उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से कार्यकर्ताओं में विश्वास पैदा किया। हमने पूरे वर्ष उनकी यादों को रोशन किया लेकिन अब हमें उसी आधार पर अपना जीवन बनाना होगा।

उन्होंने कहा कि पुराने समय की प्रतिकूलता सद्गुण के अनुकूल थी, लेकिन वर्तमान की अनुकूलता सद्गुण के प्रतिकूल है। इस चुनौती से निपटने के लिए और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है। आज हालात बदल गए हैं। समाज की दशा बदल गई है। लेकिन दत्ताजी द्वारा दिखाई दिशा नहीं बदली है। उन्होंने अभाविप कार्यकर्ताओं से कहा कि हर परिस्थिति में कार्यकर्ताओं की दिशा सही रहनी चाहिए और संगठन की दिशा नहीं बदलनी चाहिए।

समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि दत्ताजी ने कार्यकर्ताओं को अपने जीवन दर्शन से संस्कारित कर व्यक्तित्व विकास का कार्य किया। दत्ताजी न केवल एक समर्पित, मेहनती कार्यकर्ता थे, बल्कि एक अजातशत्रु भी थे। विरोधी भी उनका सम्मान करते थे। इसलिए उनके दिखाए रास्ते पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री गडकरी ने नागपुर विद्यापीठ में बनने वाले नए दीक्षांत सभागार तथा टेकड़ी गणेश मंदिर से नागपुर विद्यापीठ मार्ग पर बने पुल का नाम दत्ताजी के नाम पर करने की घोषणा भी की।

दत्ताजी के विचार और कार्य पद्धति को अभाविप कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणादायक बताते हुए अभाविप संगठन मंत्री आशीष चौहान ने कहा

कि उनकी दृष्टि अखिल भारतीय रही और उनके विभिन्न प्रयोगों से अभाविप का इतना विस्तार हुआ है। जिस संगठन के विषय में कहा जाता था कि पांच व्यक्तियों ने मिलकर आरंभ किया है, वह अब पचास लाख से अधिक कार्यकर्ताओं वाला संगठन बन गया है।

समारोह में देवनाथ मठ (श्रीक्षेत्र अंजनगाव-सुर्जी) के स्वामी जितेंद्रनाथ महाराज ने दत्ताजी को याद करते हुए उन्हें ऋषितुल्य व्यक्तित्व का धनी बताते हुए उनके दिखाए गए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। समारोह में शिक्षा और सामाजिक सेवा कार्यों में उल्लेखनीय योगदान के लिए ओंकार विद्यालय (संभाजीनगर) को दत्ताजी डिडोलकर शिक्षा पुरस्कार प्रदान किया गया। इस अवसर पर दत्ताजी डिडोलकर के जीवन पर आधारित पुस्तक 'आधारवड' के दूसरे संस्करण के साथ ही एक स्मारिका का विमोचन भी किया गया। समारोह में अभाविप के पूर्व राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील आंबेकर, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री प्रफुल्ल आकांत, संस्कार भारती के संगठन मंत्री संजय पाचपोर, अभाविप के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री श्रीहरी बोरीकर, हरेन्द्र प्रताप, पूर्व सह संगठन मंत्री जी. लक्ष्मण, स्वागत समिति मंत्री अजय संचेती, संयोजक भुपेंद्र शहाणे एवं लेखक अरुण करमरकर सहित बड़ी संख्या में अभाविप कार्यकर्ता उपस्थित थे।

जानकारी हो कि अभाविप के संस्थापन काल के अग्रणी कार्यकर्ता, पूर्व मद्रास प्रांत के संघ प्रचारक, कन्याकुमारी में विवेकानंद शिला स्मारक के प्रेरणास्रोत दत्ताजी डिडोलकर की जन्मशती का उद्घाटन समारोह गत वर्ष 6 अगस्त को नागपुर में हुआ था। जन्म शताब्दी वर्ष के दौरान देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इनमें दत्ताजी के नाम पर सड़क का नामकरण, दत्ताजी की एक भित्ति चित्र बनाने की अनूठी पहल, प्रसिद्ध आध्यात्मिक मार्गदर्शक श्री एम. का भारत की अवधारणा पर व्याख्यान, गरीब और मेघावी छात्रों की उच्च शिक्षा प्राप्त करने में आने वाली आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए दत्ताजी डिडोलकर विद्यार्थी विकास निधि की पहल, दत्ताजी के जीवन चरित्र पर आधारित 'आधारवड' एवं 'आधारवड' का हिंदी अनुवाद एवं दत्ताजी की स्मृति में शिक्षा क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार भी शामिल हैं।

प्रतिभाशाली, प्रभावशाली और प्रेरणादायक व्यक्तित्व वाले दत्ताजी डिडोलकर के विचारों की स्पष्टता उनके व्यक्तित्व की विशेषता थी। वह अभाविप की आधारशिला थे। कन्याकुमारी में विवेकानंद शिला स्मारक के निर्माण की प्रक्रिया में पहले संघर्ष को प्रज्ज्वलित करने से लेकर नागपुर विश्वविद्यालय के कार्य और निर्णय लेने की प्रक्रिया का मार्गदर्शन करने तक और फिर जयंत ट्यूटोरियल कक्षाओं के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में एक और प्रयोग करने तक उन्होंने कई रिकॉर्ड स्थापित किए। माय होम इंडिया नामक पहल से उन्होंने उत्तर-पूर्व और शेष भारत में सांस्कृतिक अंतर को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दत्ताजी का पूरा जीवन विद्यार्थी केंद्रित था। उन्होंने अपना जीवन छात्र आंदोलन को समर्पित कर दिया। दत्ताजी के समग्र व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन कार्यों को याद रखने और उनकी उपलब्धियों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से अभाविप ने उनकी जन्मशती पर वर्ष भर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। ■

प्रतिभाशाली, प्रभावशाली और प्रेरणादायक व्यक्तित्व वाले दत्ताजी डिडोलकर के विचारों की स्पष्टता उनके व्यक्तित्व की विशेषता थी। वह अभाविप की आधारशिला थे। कन्याकुमारी में विवेकानंद शिला स्मारक के निर्माण की प्रक्रिया में पहले संघर्ष को प्रज्ज्वलित करने से लेकर नागपुर विश्वविद्यालय के कार्य और निर्णय लेने की प्रक्रिया का मार्गदर्शन करने तक और फिर जयंत ट्यूटोरियल कक्षाओं के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में एक और प्रयोग करने तक उन्होंने कई रिकॉर्ड स्थापित किए।

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

पुण्यश्लोक देवी अहिल्याबाई

■ चेतस भाई सुखाड़िया

संपूर्ण विश्व में भारत भूमि यह एक ऐसी अद्भुत धरा है, जहां आदिकाल से ऋषि मुनि, संत-महात्मा, विचारक, वीर योद्धा, सम्राट, क्रांतिवीर एवं समाज सुधारक अवतरित हुए हैं। साथ ही ऐसी दिव्य मातृशक्ति, वीर माताओं, आध्यात्मिक नारियों एवं वीरांगनाओं का भी अवतरण हुआ है, जिन्होंने अपने अदम्य साहस, तप, त्याग, सात्विक जीवन एवं समाज सेवा का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। समृद्ध भारत के गौरवशाली इतिहास में नारियों की शक्ति और सामर्थ्य का प्रसंग वेदों से लेकर पुराणों तक मिलते हैं और उनके गुणों की प्रशंसा संहिताओं में भी अंकित है।

भारत की नारी न केवल अपने सौंदर्य के लिए, अपितु अपने कौशल, प्रतिभा, सैन्यशक्ति, मनोबल और दृढ़ संकल्प के साथ समाज के लिए किए गए कार्यों के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध हैं। इनमें से कुछ महिलाओं ने भारत के इतिहास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिनमें एक नाम महारानी पुण्यश्लोक देवी अहिल्याबाई होल्कर का है। देवी अहिल्याबाई होल्कर की सोच की व्यापकता ही तो थी जो कि उन्होंने अपने राज्य की सीमाओं के बाहर भी सम्पूर्ण भारत के प्रसिद्ध तीर्थस्थान में मंदिर, घाट और बावड़ियों का निर्माण कराया, मार्ग बनवाए, भूखों के लिए अन्न क्षेत्र खोलें, मंदिरों में शास्त्रों के मनन, चिंतन और प्रवचन हेतु विद्वानों की नियुक्ति की तथा आत्मप्रतिष्ठा के झूठे मोह का त्याग करके सदा न्याय करने का प्रयास अपने जीवन के आखिरी क्षणों तक करती रहीं। अहिल्यादेवी अपनी न्याय-व्यवस्था एवं न्यायप्रियता के लिए पहचानी जाती थीं। उनको लोकमाता की उपाधि जनता ने ही प्रदान की थी। पेशवा सरकार ने उनकी लोकमंगल, प्रजावत्सल, समदृष्टि तथा कर्तव्यदृष्टि की अनेक बार सराहना की थी।

देवी अहिल्याबाई का जन्म 31 मई' 1725 को महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास बीड़ जिले के एक 'छोटे से गांव 'चौंडी' में पिता मनकोजी एवं माता सुशीला शिंदे के घर

हुआ था। अगर व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो मराठी में 'अहिल्या' शब्द 'अहल्या' शब्द का अपभ्रंश माना जाता है और मराठी में अहल्या का अर्थ होता है-ऐसी भूमि, जिसे जोता न गया हो। हिंदू ग्रंथों के अनुसार गौतम ऋषि की पत्नी का नाम भी अहल्या था। कन्याओं और स्त्रियों को न पढ़ाए जाने वाले दौर में भी, उनके पिता द्वारा उनको पढ़ना-लिखना सिखाया गया। एक सामान्य व्यक्ति की तरह अहिल्या भी सीधी एवं सरल कन्या थी, परंतु विपरीत परिस्थितियों से घिरे रहते हुए भी वह परिस्थितियां उनकी मानसिक एवं भावनात्मक शक्ति को डगमगा नहीं पाई, न तो उनके व्यक्तित्व में अंतर आया, न ही उनके जीवन की परिभाषा में। स्वभाव की नैसर्गिक सरलता उन्हें विरासत में ही मिली थी। उनका मन सादगी और शांत स्वभाव भी रखता था। विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने शिव के प्रति नित्य पूजन करना और मन की सादगी को कभी

नहीं खोया। बिना किसी लोभ के शिव-पूजन आत्मसंतुष्टि, आत्मसमर्पण एवं निष्ठा से मिली आध्यात्मिक शांति एवं शक्ति ने उन्हें महारानी बनाकर जनकल्याण के कार्यों के माध्यम से सेवा का अवसर दिया।

इतिहास बताता है कि एक बार इंदौर के महाराज मल्हारराव होल्कर पुणे जाते समय मार्ग में पथडरी गांव के जिस शिवालय में रुके, वहीं अहिल्या नित्य पूजन करने आती थी। महाराज मल्हारराव के ठहराव के कारण उस जगह की आभा बदल गई थी। हाथी, घोड़े, रथ और सैनिकों की चहल-पहल तो थी, लेकिन अहिल्या पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह अपने आध्यात्मिक भाव में मंदिर की ओर नित्य पूजन के लिए चली गई। आठ वर्ष की अहिल्या की गंभीरता और विश्वास ने महाराज मल्हारराव को प्रभावित किया। परिणामस्वरूप महाराज ने अहिल्या बाई के पिता मनकोजी से अहिल्या को अपनी पुत्रवधू बनाने की इच्छा प्रकट की। इस इच्छा को मनकोजी ने स्वीकार कर सूबेदार मल्हार राव के एकमात्र पुत्र खंडोजी से 1737 में अहिल्या का विवाह कराया। 1741 में सूबेदार मल्हारराव ने इंदौर की खान नदी के किनारे राजमहल बनवाया, जो आज इंदौर के राजवाड़ा के रूप में पहचाना जाता है।

विवाह के बाद अहिल्याबाई मालवा राज्य में अपने ससुराल आ गईं। वहां शीघ्र ही अपने धर्मपरायण, सरल, दयालु एवं गरीबों के प्रति करुणा रखने वाले स्वभाव के कारण ससुराल में परिवार के सदस्यों के बीच ही नहीं, बल्कि राज्य की जनता की बीच भी लोकप्रिय बन गईं।

परंतु, 1754 में पति खांडेराव एक युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए और अहिल्याबाई मात्र 29 वर्ष की उम्र में ही विधवा हो गईं। हालांकि पति की मृत्यु के बाद अहिल्याबाई सती होना चाहती थीं, परंतु पिता समान ससुर ने उन्हें सती बनने से रोका और प्रजाहितरक्षण के लिए सामाजिक कर्तव्य करने का आग्रह किया। इसके बाद मलहारराव उन्हें राज्य के कार्यों में रुचि उत्पन्न करने और प्रोत्साहित करने लगे एवं अहिल्याबाई राज्य के कार्यों को पूरी तल्लीनता के साथ सीखने लगीं।

अहिल्याबाई महारानी तो बन गई थी, लेकिन उनका जीवन संन्यासिनी, तपस्विनी जैसा पवित्र, तेजस्वी, निर्लेप और निरासक्त। यहीं से देवी अहिल्याबाई के जीवन को अलग मोड़ मिला। वह अत्यंत कुशलता से राज्य प्रशासन के पाठ मल्हारराव से ग्रहण करने लगी। 1761 में मां की ममता से उन्हें संभालने वाली उनकी सासू मां गौतमाबाई और फिर 1764 में ससुर मल्हारराव की मृत्यु हो गई। मल्हारराव की मृत्यु के बाद अहिल्याबाई के बेटे मालेराव होल्कर ने शासन की बागडोर को संभाला। उनका पुत्र अपने दादाजी जैसा दूरदर्शी एवं राजनीति कुशल नहीं था। दायित्व बोध की कमी एवं व्यवहार में बचपना के कारण वह अपनी प्रजा में अपनी साख भी नहीं बना सका। इससे व्यथित होकर देवी अहिल्याबाई ने अपने पुत्र को महेश्वर में स्थानबद्ध कर दिया। लेकिन 1767 में मालेराव के निधन से अहिल्याबाई पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इसी बीच अहिल्याबाई की पुत्री मुक्ताबाई और उसके पति यशवंत राव फणसे का एक मात्र पुत्र नत्थूबा जो जन्म से ही दुर्बल था, तपेदिक ने उसे जकड़ लिया, जिससे उसकी भी मृत्यु हो गई। यशवंत राव भी इस सदमे को नहीं सह पाए और फिर उनकी भी मृत्यु हो गई। ऐसी स्थिति में मुक्ताबाई ने पति के साथ सती होने का निश्चय किया। देवी अहिल्याबाई ने मुक्ताबाई को बहुत समझाया, अपनी कन्या के निर्णय को वह बदल नहीं पाई।

संकट की इस घड़ी में अहिल्याबाई ने बहुत ही धैर्य से काम लिया और अपने राज्य की जनता के हित में राज्य की बागडोर को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। यह वह काल था, जब अंग्रेज भारत में लगातार अपने पैर पसारते जा रहे थे। ऐसी विकट परिस्थितियों में राजमाता ने जिस प्रकार सफलतापूर्वक शासन को चलाया वह चिरस्मरणीय है। उनके 28 वर्षों के शासनकाल में मालवा राज्य की राजधानी महेश्वर, साहित्य, संगीत, कला और उद्योग का केंद्र बिंदु बन गई थी। वास्तव में उस काल में जो आदर्श राज्यकर्ता हुए, उनमें से एक देवी अहिल्याबाई थीं। उन्होंने प्रजा हित में कल्याणकारी कार्य किए और प्रजा के सभी अंगों की चिंता करते हुए राज्य में सुराज कायम किया।

उनकी शासन व्यवस्था का सबसे बड़ा बदलाव सेना को राज्य से अलग करना था। विश्वासपात्र सूबेदार तुकोजीराव होल्कर को उन्होंने अपना सेनापति बनाया था, जिनके पास सेना की पूरी कमान थी। महारानी अहिल्याबाई ने शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी स्वयं अपने पास रखी। अपना स्वयं का खर्च वह अपने संचित धन से करती थी, जिससे शासन व्यवस्था में उन्होंने एक

अलग स्तर की पारदर्शिता को स्थापित किया। राज्य में नियमबद्ध न्यायालय, ग्राम पंचायतों को न्यायदान का व्यापक अधिकार, महिला सशक्तिकरण के लिए विधवा महिलाओं के हितों संबंधी कानूनों को लागू करना, विधवा महिलाओं को पति की सम्पत्ति और पुत्र गोद लेने का अधिकार आदि उनके शासन की विशेषताओं के रूप में देखा जा सकता है। ऐसी पुण्यश्लोक देवी अहिल्याबाई होल्कर महिलाओं के कर्तव्य की क्षमता की प्रतीक हैं। मातृशक्ति के सशक्तिकरण का अनुकरण आदर्श देवी अहिल्याबाई ने अपने जीवन से सभी के सामने रखा।

अपने देश की संस्कृति का जो आधार है, उसको पुष्ट करने के लिए देश में अनेक स्थानों पर उन्होंने मंदिर बनवाए। स्वयं राज्य करने के बाद भी स्वयं को कभी राजा नहीं स्वीकार किया। उन्होंने कई जगह मंदिर बनवाए, नदियों पर घाट बनवाए, धर्मशालाएं बनवाईं और यह कार्य उन्होंने संपूर्ण भारत में किया। धर्मयात्राओं और व्यापारिक मार्ग पर यह सारे कार्य कराए, जिससे देश की सारी जनता का अपने सांस्कृतिक स्थलों में और अपनी आजीविका के लिए आवागमन सर्वत्र चलता रहे और एकात्मता बनती रहे। उन्होंने यह सारा काम अपनी निजी संपत्ति में से किया। देवी अहिल्याबाई के परोपकारी कार्य का अगर कोई उदाहरण देखें तो उन्होंने अपने कार्यों से संपूर्ण भारतवर्ष को जोड़ने का प्रयास किया।

काशी में विश्वनाथ मंदिर के निर्माण में देवी अहिल्याबाई का योगदान और वही प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट, जनाना घाट, रामेश्वर पंचकोशी धर्मशाला, कपिलधारा धर्मशाला, नगवा बगीचा, मणिकर्णेश्वर मंदिर, अहलेश्वर मंदिर, ऋषि अगस्ता कुंड, भगवान काशी विश्वनाथ मंदिर के समीप पांच मंडपों से सुशोभित मंदिर और तारकेश्वर में मंदिर का निर्माण आज भी उनके योगदान को सामने रखता है।

देवी अहिल्याबाई प्रजा का पालन, राज्य का संचालन, राज्य की सुरक्षा, देश की एकात्मता-अखंडता, सामाजिक समरसता, सुशीलता और सादगी, इनका आदर्श रखने वाली एक महिला राज्यकर्ता थी। पुण्यश्लोक देवी अहिल्याबाई वर्तमान स्थिति में एक आदर्श हैं। मल्हारराव जब तक जीवित थे, तब तक रामपुरा के चंद्रावत उनके अधीन रहे। उनकी मृत्यु के पश्चात चंद्रावतों ने होल्कर राज्य पर यह समझकर आक्रमण किया कि मल्हारराव नहीं रहे तो होल्करों के अधीन क्यों रहें? और अहिल्याबाई एक अबला स्त्री है, वह कुछ नहीं कर सकती। यह सोच लेकर वह अहिल्याबाई के राज्य पर आक्रमण करते रहे। एक बार अहिल्याबाई ने चंद्रावत को माफ कर छोड़ दिया था, किंतु चंद्रावत बार-बार आक्रमण करते रहे। लेकिन तीसरी बार उन्होंने अपने सेनापति शरीफ भाई को चंद्रावतों पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। चंद्रावतों और होल्कर सेना का घमासान युद्ध हुआ और युद्ध का संचालन अहिल्याबाई ने किया। चंद्रावतों के सेनापति सौभाग्यसिंह को अहिल्याबाई ने तोप से उड़ा दिया। विजय के उपलक्ष्य में होल्करों की सेना ने इंदौर, महेश्वर और पुणे में विजय उत्सव मनाया और संपूर्ण मराठा साम्राज्य में शिव-भक्त अहिल्याबाई वीरांगना के रूप में पहचानी जाने लगी।

इंदौर को 'अहिल्या की नगरी' कहा जाता है। आज 21वीं शताब्दी में पर्यावरण की बातें कही जाती हैं, किंतु अहिल्याबाई के कार्यकाल में प्रत्येक किसान को बड़, पीपल, नीम आदि के नए बीस-बीस वृक्ष लगाना अनिवार्य था। मार्ग के दोनों ओर छायादार वृक्ष लगाए जाते थे। बंजर भूमि पर भील, गोंड आदिवासियों द्वारा वृक्ष लगाने से उन्हें रोजगार मिलता था। उनके शासनकाल में वृक्षों को काटना या तोड़ना जुर्म था।

उनके जीवन के अंतिम समय में श्रावण माह चल रहा था। श्रावण माह में अहिल्या देवी बारह से लेकर तेरह हजार ब्राह्मणों को भोजन कराती थीं। हर वर्ष की भांति श्रावण माह में उन्होंने ब्राह्मण-भोज का संकल्प किया। माहेश्वर में ब्राह्मण भोज चल रहे थे। मंदिरों में भजन-कीर्तन की पवित्रता फैल रही थी। लेकिन मराठाशाही के भविष्य और होल्कर सत्ता को लेकर वह उदास हो जाती थीं। मृत्यु समीप आ रही है। यह जानकर, धर्म विधि के अनुसार अहिल्याबाई ने कुछ गायें दान में दीं। अपने राजदरबार में, राजवाड़े में उन्होंने ईश्वर का नामस्मरण, नामघोष शुरू किया। लेकिन थकान के कारण वह लेट गईं। उनकी नजरों के सामने गंगा किनारे स्थित काशी विश्वेश्वर आ रहे थे। शिवस्तुति का घोष चारों ओर गूंज रहा था। घोष को सुनते-सुनते 13 अगस्त' 1795 को अहिल्याबाई चिरनिद्रा के अधीन हो गई। एक सुखदा, वैरदा, मंगला, कल्याणी महारानी का महापर्व समाप्त हो गया और एक पुण्यश्लोक आत्मा अनंत में विलीन हो गई। ■

प्रदर्शन कर रहे अभाविप कार्यकर्ताओं पर पुलिस का लाठीचार्ज

नगरीय व्यवस्थाओं के कुप्रबंधन के कारण कोचिंग छात्रों की असामयिक मौत

देश की राजधानी दिल्ली के राजेन्द्र नगर स्थित एक कोचिंग केंद्र में जलभराव के कारण हुई छात्रों की असामयिक मौत के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने दिल्ली सरकार एवं दिल्ली नगर निगम के महापौर आवास के बाहर विरोध-प्रदर्शन किया। गत 28 जुलाई को किए गए प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया, जिसमें कई छात्र चोटिल हुए।

अभाविप ने पुलिस कार्रवाई की कठोर निंदा करते हुए आरोप लगाया कि यह छात्रों की आवाज़ को दबाने का कुत्सित प्रयास है और अभाविप ऐसे प्रयासों से डरने वाली नहीं है। अभाविप का स्पष्ट मानना है कि यह घटना घोर भ्रष्टाचार में लिप्त दिल्ली सरकार एवं दिल्ली नगर निगम की मिलीभगत एवं लापरवाही से हुई है और दिल्ली सरकार एवं नगर निगम की विफलताओं को उजागर करती है। इसलिए छात्रों की आसमयिक मौत के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

अभाविप ने सभी शैक्षणिक संस्थानों एवं कोचिंग केंद्रों में सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने, शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थानों के बुनियादी ढांचे की नियमित जांच और सुधार सुनिश्चित करने एवं ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र निगरानी समिति का गठन करने की मांग की है।

अभाविप दिल्ली प्रांत मंत्री हर्ष अत्री ने कहा कि अभाविप दुर्भाग्यपूर्ण घटना में मृत छात्र-छात्राओं के परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करती है। घटना से स्पष्ट होता है कि दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार किस स्तर तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। राजेंद्र नगर में घटित घटना को लेकर वामपंथी छात्र संगठन गलत दिशा देने

का काम कर रहे हैं। जहां एक तरफ अभाविप कार्यकर्ता छात्रों को न्याय दिलाने के लिए लाठी की मार झेल रहे हैं, वहीं वामपंथी मानसिकता के लोग छात्रों के मुद्दे से हटकर अपना एजेंडा थोपने की कोशिश में लगे हैं।

घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अभाविप की राष्ट्रीय मंत्री शिवांगी खरवाल ने छात्रों की मृत्यु को दुखद बताया। उन्होंने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार दोनों चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार तथा दिल्ली नगर निगम ने नालों की सफाई तथा अन्य आवश्यक कदम अगर पहले ही उठा लिए होते तो यह घटना नहीं होती। उन्होंने देशभर के कोचिंग संस्थानों के नियमन के लिए उचित नीति बनाने के साथ ही कोचिंग संस्थानों के कुप्रबंधन से हो रही घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की मांग की। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

लापरवाही और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई तीन विद्यार्थियों की जिंदगी

■ अभिषेक रंजन

राजधानी दिल्ली के राजेंद्र नगर स्थित एक भवन के तहखाने में अचानक पानी भर जाने से तीन विद्यार्थियों की दर्दनाक मौत हो गई। छात्रों की असामयिक मौत से पूरा देश स्तब्ध रह गया। भवन में एक कोचिंग केंद्र चलाया जा रहा था। भारी वर्षा के कारण जिस तहखाने में अचानक पानी भरने की अप्रत्याशित घटना हुई, उस तहखाने में अवैध ढंग से छात्रों को एकत्र करके शिक्षण कार्य हो रहा था। देश के तीन अलग-अलग राज्यों से दिल्ली आकर शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों की असमय मृत्यु के बाद कोचिंग केंद्रों की व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न एक बार फिर पैदा हो गए। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह रही कि दिल्ली में नगरपालिका से लेकर विधानसभा तक शासन करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार और उसके नेताओं ने दर्दनाक घटना की जिम्मेदारी लेने के स्थान पर उपराज्यपाल और केंद्र सरकार पर आरोप लगाकर अपना पल्ला झाड़ने का प्रयास किया। वैसे यह पहली घटना नहीं है, जहां आम जनता की मौत के बाद दोषारोपण करने में व्यस्त लोग अपनी जिम्मेदारियों से बचते नजर आए। ऐसा पहले भी होता रहा है और ऐसा ही एक बार फिर हुआ।

गत जुलाई माह में भारी वर्षा के बाद सड़क पर जमा हुआ पानी अचानक तहखाने में भर जाने से राजेंद्र नगर में हुई घटना से पहले मुखर्जी नगर में बिजली के तार की चपेट में आने से एक अन्य विद्यार्थी की मौत हो गई थी। यह विद्यार्थी केंद्रीय सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहा था। इसी तरह मुखर्जी नगर में ही एक कोचिंग केंद्र में आग लगने की घटना और बच्चों की जान बचाने की कोशिशों वाली तस्वीरों ने देश को चिंतित कर दिया था। उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करते हुए दिल्ली के सभी कोचिंग केंद्रों की जांच के निर्देश भी दिए थे। लेकिन वास्तविकता में कोचिंग केंद्रों पर नकेल कसने का कोई प्रयास किया ही नहीं गया। राजेंद्र नगर में हुई विद्यार्थियों की असामयिक मौत ने दिल्ली की सरकारी नियामक व्यवस्था की घोर लापरवाही और बेलगाम भ्रष्टाचार को भी उजागर किया है।

घटना की बाद लीपापोती के लिए गिरफ्तारियां करके कार्रवाई का नाटक अवश्य किया गया, लेकिन दिल्ली नगर निगम के उन कर्मचारियों और अधिकारियों पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई, जिनके संरक्षण में तहखाने में पुस्तकालय के साथ ही अवैध तरीके से शिक्षण कार्य किया जा रहा था। राजनेता, अधिकारी एवं कर्मचारियों की मिलीभगत से दिल्ली का नगरीय ढांचा चरमरा गया है। अनियोजित विकास और नगर निर्माण संबंधी नियम-कानूनों के सार्वजनिक उल्लंघन, अव्यवस्था और अनदेखी का एक उदाहरण राजेंद्र नगर में हुई तीन विद्यार्थियों की असामयिक मौत के रूप में भी देखा जा सकता है।

यहां पर ध्यान देने वाले तथ्य यह भी है कि केंद्र सरकार ने न केवल जनवरी 2024 में, बल्कि 2017, 2019, 2020 और 2023 में दिशा-निर्देश जारी करके कोचिंग केंद्रों के नियमन, पंजीकरण एवं निगरानी से जुड़े पहलुओं पर ध्यान देने के लिए कहा था। लेकिन दिल्ली सरकार ने इन दिशा-निर्देशों पर ध्यान ही नहीं दिया। अगर दिया होता, तो शायद ऐसी स्थिति कभी नहीं आती।

दिल्ली सरकार की कार्यप्रक्रिया पर प्रश्न उठाने वाली राजेंद्र नगर की घटना नहीं हुई होती, अगर सरकार ने गत 26 जून को एक छात्र द्वारा की गई शिकायत पर तुरंत संज्ञान लिया होता। शिकायतकर्ता

छात्र ने बिना अनुमति के तहखाने में कक्षा चलाए जाने की जानकारी देकर कार्रवाई करने की मांग की थी। वर्षा ऋतु आने से पहले दिल्ली सरकार एवं दिल्ली नगर निगम ने वर्षा से जमा होने वाले जल की निकासी के सम्बन्ध में बड़े-बड़े दावे तो किए थे, लेकिन वास्तविकता में जन सरोकारों के प्रति सरकार की लापरवाही तीन विद्यार्थियों की असमय मौत का कारण बन गई।

देश की राजधानी को विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त नगर बनाने का दावा करने वाले आप सरकार के कार्यकाल के दौरान अनेकों ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जो दिल्ली की ध्वस्त होती व्यवस्था का संकेत दे रही हैं। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। वर्षाकाल में पूरी दिल्ली पानी से भर जाती है, जबकि वर्षा से पहले पानी के लिए त्राहिमाम करती है। सर्दियों के मौसम में दिल्ली की जनता स्वच्छ वायु के लिए तरसती है और भीषण गर्मी में बिजली कटौती की मार सहती दिखाई देती है। वर्षा काल में जल जमाव रोकने के लिए पहले नालों की सफाई का दावा करने हुए लाखों रुपए का खर्च दिखाया जाता है, लेकिन सफाई व्यवस्था की पोल वर्षा होने के बाद खुलने लगती है। दिल्ली का शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा, जहां गलियों में जल-जमाव और बदबूदार पानी से स्थानीय निवासी परेशान नहीं होंगे।

दिल्ली की व्यवस्था में जनमानस का विश्वास पुनर्स्थापित करना अब आवश्यक होता जा रहा है। राजेंद्र नगर में हुई असामयिक घटना की जांच कर दोषियों को दंडित करने के लिए केंद्र सरकार को पहल करनी चाहिए। साथ ही भवनों में अग्नि सुरक्षा से लेकर जल-निकासी जैसे विषयों पर राजनीति को किनारे करके सटीक निर्णय लिए जाने चाहिए। कोचिंग केंद्रों पर केंद्र द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को सख्ती से लागू करने की प्रबल आवश्यकता है, ताकि राजेंद्र नगर जैसी घटना पुनः न होने पाए। साथ ही कोचिंग केंद्रों की अवैध गतिविधियों एवं कार्यों को संरक्षण देने वाले भ्रष्ट अधिकारियों, कर्मचारियों एवं जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। कोचिंग केंद्रों की मनमानी को रोकने के लिए एक विधिवत हेल्पलाइन भी प्रारम्भ की जानी चाहिए, जिससे विद्यार्थी सुरक्षित महसूस कर सकें। ■

। निर्णय ।

जेएनयू में स्थापित होंगे हिन्दू, बौद्ध और जैन धर्म अध्ययन केंद्र

देश की राजधानी स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में हिन्दू, बौद्ध और जैन धर्म के अध्ययन के लिए नए केंद्र स्थापित किए जाएंगे। यह केंद्र विश्वविद्यालय के संस्कृत और भारतीय अध्ययन स्कूल के अंतर्गत होगें तथा यहां छात्र प्राचीन भारतीय परंपरा में शोध कर सकेंगे। हिन्दू, बौद्ध एवं जैन अध्ययन केंद्र स्थापित करने का निर्णय गत 29 मई को विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद की बैठक में लिया गया था, जिसे विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया है। गत 9 जुलाई को विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना में बताया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति और भारतीय ज्ञान प्रणाली के कार्यान्वयन का पता लगाने और सिफारिश करने के लिए जेएनयू द्वारा गठित समिति की सिफारिश को स्वीकार करके संस्कृत और भारतीय अध्ययन स्कूल के तहत हिन्दू, बौद्ध और जैन अध्ययन के लिए केंद्रों की स्थापना हेतु कार्यकारी परिषद ने अपनी अनुमति प्रदान कर दी है। इन केंद्रों की स्थापना से जेएनयू में छात्रों को हिन्दू, बौद्ध और जैन धर्म के सम्बन्ध में गहन अध्ययन करते हुए परास्नातक एवं शोध करने का अवसर मिलेगा। अध्ययन केंद्र में छात्रों को प्रवेश केंद्रीय विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा (सीयूसीईटी) में माध्यम से होगा। चूंकि इस वर्ष सीयूईटी-पीजी परीक्षा हो चुकी है। इसलिए छात्रों को अगले सत्र से इन केंद्रों में प्रवेश मिलेगा। आरम्भ में तीनों केंद्रों में बीस-बीस सीटें होंगी, जिन्हे आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकेगा। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

पारंपरिक भारतीय खेल संस्कृति को बढ़ावा देने की आवश्यकता

■ प्रदीप शेखावत

राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ ही युवाओं को विभिन्न खेलों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। देश के खेल, खिलाड़ियों और खेल के विकास के लिए समर्पित राष्ट्रीय खेल दिवस वैश्विक मंच पर देश को गौरवान्वित भी करता है। यह दिवस न केवल खेल को, बल्कि स्वस्थ रहने के महत्व को भी दर्शाता है। देश के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा भी कई बार इसी दिन होता है, जिसमें छह अलग-अलग श्रेणी में दिए जाने वाले पुरस्कार शामिल है।

भारत में पहला राष्ट्रीय खेल दिवस 2012 में मेजर ध्यानचंद की 107 वीं जयंती के दिन आरम्भ हुआ था। हॉकी के जादूगर नाम से विख्यात मेजर ध्यानचंद ने 1928, 1932 और 1936 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत को ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलाने के साथ ही अपनी पहली हैट्रिक पूरी की थी। उन्होंने 1926 से 1949 के मध्य भारत के लिए कुल 570 गोल किए।

भारत में खेलों का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। प्राचीन काल में विभिन्न खेलों की काफी लोकप्रियता थी। इसका कारण यह था कि खेलों के माध्यम से ही उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता था। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में कई पारंपरिक खेलों का उल्लेख है, जो भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा हैं। रामायण में राम और लक्ष्मण द्वारा धनुष-बाण का खेल, उनकी युद्धकला और कौशल को दर्शाता है। इसमें कुश्ती और मल्ल युद्ध का भी उल्लेख है, जो शारीरिक बल और साहस को सामने लाता है। महाभारत में अर्जुन द्वारा मछली की आंख पर निशाना साधना, उनकी धनुर्विद्या कौशल का प्रतीक है। कौरवों और पांडवों के बीच गदा युद्ध शारीरिक शक्ति और युद्धकला का प्रदर्शन करता है। पांडवों द्वारा खेला जाने वाले जुए का खेल, शतरंज जैसी खेलों की शुरुआत को भी संकेत करता है। यह सभी प्राचीन खेल, न केवल मनोरंजन का माध्यम थे, बल्कि शारीरिक और मानसिक विकास का भी हिस्सा थे। यह खेल भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण अंग होने के साथ ही आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं।

मुगलकाल में भारतीय खेलों से ज्यादा पोलो (चौगान) लोकप्रिय था, जिसे शाही खेल माना जाता था। शिकार मुग़ल शासकों का प्रिय खेल था, जिसे साहस और युद्धकला के अभ्यास के रूप में देखा जाता था। कबूतरबाजी भी मुग़ल शासकों की पसंदीदा गतिविधि थी, जिसमें कबूतरों के बीच प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की जाती थीं।

भारत के प्राचीन खेल

मल्ल युद्ध : मल्ल युद्ध का इतिहास बेहद ही पुराना है। बलराम, हनुमान, भीम, जामवंत और जरासंध इत्यादि मल्ल युद्ध के लिए ही प्रसिद्ध थे। धीरे-धीरे यह मल्ल युद्ध कुश्ती में परिवर्तित हो गया। कुश्ती का उदय दक्षिण भारत में हुआ था। कुश्ती को अति प्राचीन खेल कहा जाता है जो कि कला और मनोरंजन का साधन भी रहा है। कुश्ती को प्रतिष्ठा का भी खेल कहा जाता था, जिसमें दो पक्ष अपने-अपने मजबूत पहलवानों को मैदान पर उतारते थे।

तीरंदाजी : भारत के इतिहास में तीरंदाजी बेहद ही पुराना खेल है। रामायण और महाभारत काल में भी तीरंदाजी हुआ करती थी। क्षत्रियों को प्रशिक्षण देने के लिए तीरंदाजी का प्रयोग किया जाता था जो बाद में एक खेल में बदल गया। तीरंदाजी को लेकर गुरुकुल में इसकी प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती थी।

शतरंज : शतरंज को दिमाग का खेल कहा जाता है। इसकी आविष्कारक रावण की पत्नी मंदोदरी को माना जाता है। मंदोदरी का उद्देश्य यह था कि रावण युद्ध में ज्यादा समय व्यतीत ना करें। इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र मेघदूत के साथ मिलकर इस खेल को प्रारंभ किया था। धीरे-धीरे यह खेल

प्रसिद्ध होता गया। इसे चतुरआंग या चतुरंगी कहा गया। बाद में इसे शतरंज का नाम दिया गया।

पोलो : पोलो का इतिहास भारत से जुड़ा हुआ है। मुगल काल के दौरान यह चौगान के रूप से जाना जाता है। हालांकि इस खेल की प्रारंभिक उत्पत्ति के बारे में कई प्रकार के दावे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसकी खोज मणिपुर में हुई थी। फिलहाल मणिपुर में इंफाल पोलो मैदान विश्व के सबसे पुराने मैदानों में से एक है।

खो-खो : भारत के इतिहास में खो-खो भी पुराना खेल है। यह मुख्य रूप से आत्मरक्षा, आक्रमण या प्रत्याक्रमण के कौशल को विकसित करने के लिए खोजा गया था। धीरे-धीरे यह खेल में परिवर्तित हो गया। खो-खो आज भी भारत के कई हिस्सों में खेला जाता है।

कबड्डी : कबड्डी एक सामूहिक खेल है जो समाज में एकता को दर्शाता है। यह खेल आत्मरक्षा या शिकार के गुणों को सिखाएं जाने के लिए भी खेला जाता है। महाभारत में भगवान कृष्ण अपने साथियों के साथ कबड्डी खेला करते थे। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया जाना भी इसी खेल का एक उदाहरण है।

भारतीय खेलों में कई बदलाव कर लॉर्ड मैकाले ने भारत के प्राचीन खेलों की समाप्त करने की कोशिश की। मैकाले के आगमन से पहले, भारतीय और पारंपरिक खेलों का व्यापक प्रचार था। सात लाख से अधिक गुरुकुलों में शारीरिक शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान था और खेलों में जातिवाद एवं अस्पृश्यता का कोई स्थान नहीं था। लेकिन मैकाले की नीतियों ने भारतीय खेलों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। उन्होंने पारंपरिक खेलों के स्थान पर पश्चिमी शिक्षा और खेलों को बढ़ावा दिया, जिससे भारतीय खेल हाशिए में चले गए और पश्चिमी खेलों को प्राथमिकता दी जाने लगी। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत के पारंपरिक खेलों को समाप्त करने या उन्हें हाशिए पर धकेलने का कार्य ब्रिटिश नीतियों, प्रशासनिक सुधारों और सांस्कृतिक प्रभावों के माध्यम से किए गए। उदाहरण को इस प्रकार को समझा जा सकता है-

क्रिकेट और पश्चिमी खेलों का प्रसार : ब्रिटिश शासन के दौरान क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल जैसे पश्चिमी खेलों को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित किया गया। इन खेलों को शिक्षा संस्थानों और क्लबों में प्रमुखता दी गई, जिससे भारतीय पारंपरिक खेलों की प्रासंगिकता कम होती चली गई।

नगरीकरण और सामाजिक परिवर्तन : ब्रिटिश शासनकाल में नगरीकरण और पश्चिमीकरण तीव्रता से हुआ। परिणामस्वरूप पारंपरिक खेलों और उनसे सम्बंधित संस्थाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। इससे देश की जनता पश्चिमी जीवनशैली और खेलों की ओर आकर्षित होने लगी।

सामाजिक और सांस्कृतिक दमन : ब्रिटिश शासन ने भारतीय संस्कृति और परंपराओं को दमन करने का प्रयास किया। इसके तहत कई पारंपरिक खेलों को "पिछड़ा" या "बर्बर" करार देकर उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया गया ।

कानूनी और प्रशासनिक हस्तक्षेप : ब्रिटिश सरकार ने कई पारंपरिक खेलों और मेलों पर प्रतिबंध लगाए या उन्हें सीमित किया। इनमें तीरंदाजी, कबड्डी और मल्लयुद्ध जैसे खेल शामिल थे।

> **मैकाले की नीतियों ने भारतीय खेलों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। उन्होंने पारंपरिक खेलों के स्थान पर पश्चिमी शिक्षा और खेलों को बढ़ावा दिया, जिससे भारतीय खेल हाशिए में चले गए और पश्चिमी खेलों को प्राथमिकता दी जाने लगी।**

आर्थिक प्रभाव : ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के कारण भारतीय ग्रामीण और नगरीय समाज में व्यापक परिवर्तन आए। कई पारंपरिक खेलों के आयोजन के लिए आवश्यक आर्थिक संसाधन और सामाजिक संरचना धीरे-धीरे कमजोर होती चली गई।

शिक्षा और सांस्कृतिक नीतियां : ब्रिटिश शिक्षा नीतियों के माध्यम से भारतीय बच्चों और युवाओं को पश्चिमी खेलों और गतिविधियों की ओर प्रेरित किया गया। इससे पारंपरिक खेलों की प्रासंगिकता और लोकप्रियता कम हो गई।

प्रतिरोध और पुनर्जीवन : ब्रिटिश शासन के प्रयासों के बावजूद कई भारतीय पारंपरिक खेल स्थानीय समुदायों और स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं के समर्थन से जीवित रहे। स्वतंत्रता के बाद इन खेलों के पुनर्जीवन के प्रयास हुए और वह आज भी भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा हैं।

भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने पारंपरिक खेलों को संरक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास

किए। उनका मुख्य उद्देश्य भारतीय संस्कृति को स्वस्थ और औपनिवेशिक प्रभावों से मुक्त करना था।

राष्ट्रीय चेतना का प्रचार : बाल गंगाधर तिलक और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दिया और पारंपरिक खेलों को राष्ट्रीय स्वाभिमान का हिस्सा माना।

स्थानीय खेल आयोजनों का समर्थन : स्वतंत्रता सेनानियों ने स्थानीय मेलों और खेल आयोजनों का समर्थन किया, जिससे पारंपरिक खेलों के प्रति रुचि बढ़ी।

खेल संगठनों की स्थापना : स्वतंत्रता सेनानियों ने खेल संगठनों की स्थापना की, जिनका उद्देश्य पारंपरिक खेलों को संरक्षित करना और लोकप्रिय बनाना था।

शारीरिक शिक्षा और प्रशिक्षण : लाला लाजपत राय और स्वामी विवेकानंद ने शारीरिक शिक्षा के माध्यम से पारंपरिक खेलों को बढ़ावा दिया और युवाओं को प्रोत्साहित किया।

राष्ट्रीय आंदोलन में खेलों का उपयोग : खेलों का उपयोग स्वतंत्रता आंदोलन में एकजुटता और सामूहिक भावना को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया।

शिक्षा संस्थानों में खेलों का प्रोत्साहन : शांति निकेतन और काशी विद्यापीठ जैसे संस्थानों में पारंपरिक खेलों को बढ़ावा दिया गया।

सांस्कृतिक पुनर्जागरण : स्वतंत्रता सेनानियों ने भारतीय संस्कृति और खेलों के पुनर्जीवन के लिए साहित्य, कला, और सांस्कृतिक आयोजनों का सहारा लिया।

प्रचार और मीडिया : खेलों के महत्व को सामने लाने के लिए पत्रिकाओं, समाचारपत्रों और सभाओं का उपयोग किया गया।

ऐसे प्रयासों ने पारंपरिक खेलों को जीवित रखा और स्वतंत्रता के बाद भी उनकी अहमियत बनाए रखी।

1947 के बाद भारतीय खेलों में नकारात्मक विमर्श भी आया। "पढ़ेगा-लिखेगा तो नवाब बनेगा, खेलेगा-कूदेगा तो खराब होगा।" इस नकारात्मक विमर्श के कारण खेल क्षेत्र को कई समस्यायों का सामना करना पड़ा, इसे इस तरह समझा जा सकता है-

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में कमजोरी : स्वतंत्रता के बाद, भारतीय खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर सिद्ध हुए।

विभाजन का असर : विभाजन ने खेलों के विकास में बाधा डाली।

संसाधनों की कमी : उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धा के लिए संसाधनों की कमी रही।

राजनीतिक अस्थिरता : राजनीतिक उठापटक ने खेल संगठनों की कार्यक्षमता प्रभावित की।

सामाजिक परिवर्तन : सामाजिक बदलावों ने खेलों में रुचि को प्रभावित किया।

विदेशी और निजी प्रभाव : विदेशी और निजी संस्थाओं के प्रभाव के कारण भारत में खेलों का विकास प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ।

पारंपरिक भारतीय खेलों को बढ़ावा देने के लिए 'खेलो भारत' की गतिविधियां

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) गतिविधि 'खेलो भारत' के माध्यम से पारंपरिक भारतीय खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। परंपरागत खेलों में कुश्ती, अखाड़ा, थांग-ता, कलरीपायट्टु, खो-खो, रस्साकशी, मलखंब, हेक्को, स्टापु, हेक्को, छऊ और पाइका अखाड़ा, कबड्डी, शूटिंग बॉल, लागोरी और लंगडी, गतका, रोल बॉल, धूप और कौड़ी खेल, सिलंबम, तीरंदाजी, गिल्ली-डंडा समेत अन्य देशी खेलों को रखा जाता है। इन पारम्परिक खेलों के प्रचार-प्रसार से भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित किया जा सकता है और युवा पीढ़ी को अपनी पारंपरिक खेलों की ओर आकर्षित भी किया जा सकता है। 'खेलो भारत' के माध्यम से भारतीय खेलों और पारंपरिक खेलों के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी प्रकार 'फिट भारत मूवमेंट' के तहत लोगों को फिटनेस और स्वस्थ जीवन के महत्व के प्रति जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। ऐसे कार्यक्रमों से न केवल खेलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, बल्कि एक स्वस्थ, सशक्त, और प्रेरित समाज का निर्माण भी हो। सकारात्मक विमर्श यह है कि "पढ़ेगा-लिखेगा तो सफल होगा, खेलेगा-कूदेगा तो उत्कृष्ट बनेगा।" यह विचार समाज में अपनाए जाने से शिक्षा और खेल दोनों के महत्व को मान्यता मिलेगी। इसके लिए निम्नवत व्यवस्था परिवर्तन आवश्यक है-

फेडरेशन संरचना : राष्ट्रीय, राज्य, और जिला फेडरेशन में खेलों के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी या प्रमुख जानकार शामिल हों।

महिला कोच : शैक्षिक संस्थान में महिला खिलाड़ियों के लिए महिला कोच की व्यवस्था होनी चाहिए।

प्रशिक्षण और शिक्षा : विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में खेल कोच वही हों जो उस खेल का प्रशिक्षण दें और शिक्षा विशेषज्ञ वही हों, जो विषय पढ़ाएं। ■

ओलंपिक में भारत ने हासिल किए छह पदक

नीरज चोपड़ा, मनु भाकर, सरबजोत सिंह, स्वप्निल कुसाले, अमन सेहरावत और हरमनप्रीत सिंह के नेतृत्व में भारतीय पुरुष हॉकी टीम। यह वह नाम है, जिन्होंने फ्रांस की राजधानी पेरिस में संपन्न ओलंपिक खेलों में पदक हासिल करके भारत का गौरव बढ़ाया है। पेरिस में ओलंपिक खेलों का आयोजन गत 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक किया गया, जिसमें भारत सहित 205 देशों ने हिस्सा लिया।

भारत के लिए सबसे पहला कांस्य पदक मनु भाकर ने हासिल किया। साथ ही सरबजोत सिंह के साथ मिश्रित टीम प्रतियोगिता में भी कांस्य पदक जीतकर मनु एक ही ओलंपिक में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई। निशानेबाजी में तीसरा कांस्य पदक स्वप्निल कुसाले को मिला है। ओलंपिक खेलों में भारतीय निशानेबाजों का यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले 2012 के ओलंपिक खेल में भारत को निशानेबाजी में दो पदक मिले थे।

कुश्ती में एकमात्र कांस्य पदक जीतकर अमन सहरावत ने भारत के सबसे कम आयु के ओलंपिक पदक विजेता बनने का गौरव हासिल किया है, जबकि भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा अपनी चोट के कारण स्वर्ण पदक लाने से चूक गए। उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। लेकिन नीरज दो बार ओलंपिक पदक हासिल करने वाले भारत के पांचवें खिलाडी बन गए हैं। भारत के लिए एक कांस्य पदक हरमनप्रीत सिंह के नेतृत्व वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने भी हासिल किया।

भारतीय दल में शामिल कई खिलाड़ियों का प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप नहीं रहा, जिससे वह पदक हासिल करने में चूक गए। पुरुष बैडमिंटन प्रतियोगिता में लक्ष्य सेन सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय तो बन गए, पर अंतिम तीन में स्थान बना पाने में असफल रहे। इसी तरह पहलवान विनेश फोगट महिलाओं के पचास किलोग्राम वर्ग की प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने के बाद 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण अयोग्य घोषित कर दी गईं। मीराबाई चानू, पी. वी. सिंधु, दीपिका कुमारी, निकहत जरीन और लवलीना बोरगोहेन जैसे खिलाडी भी पिछड़ गए।

पेरिस ओलंपिक में भारत के 117 खिलाड़ियों के दल ने 16 खेल प्रतियोगिताओं क्रमशः तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, घुड़सवारी, गोल्फ, हॉकी, जूडो, रोइंग, सेलिंग, शूटिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस और टेनिस में भाग लिया। अबकी बार पदक तालिका में संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर रहे। पदक तालिका में भारत को 71वां स्थान मिला।

ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि देश की खेल नीति, खेल कार्यक्रम एवं खेल प्रबंधन का गंभीर मूल्यांकन करके आधुनिक समयानुसार आवश्यक सुधारों के लिए गंभीरता से कदम उठाए जाएं क्योंकि पेरिस ओलंपिक ने भारत को गंभीर अंतर्निरीक्षण करने का एक अवसर दिया है अन्यथा खेल के नाम पर अरबों रुपए खर्च करने के बाद भी ऐसे ही निराशाजनक परिणाम सामने आते रहेंगे। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

पैरालंपिक-2024 में 29 पदक

पैरालंपिक-2024 में 29 पदक हासिल करके भारत ने इतिहास में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। पैरालंपिक में भारत ने 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक जीते हैं। पैरालंपिक में दो स्वर्ण पदक जीतने वाली अवनि लेखरा पहली भारतीय महिला खिलाडी बन गई हैं। उन्होंने एयर राइफल शूटिंग स्पर्धा में हिस्सा लिया। इससे पहले 2020 में टोक्यो में आयोजित पैरालंपिक में भारत को पांच स्वर्ण सहित 19 पदक मिले थे।

फ्रांस की राजधानी में पेरिस में गत 28 अगस्त से 8 सितंबर तक हुए पैरालंपिक-2024 खेल प्रतियोगिता में भारत के 84 खिलाड़ियों ने बारह खेलों में हिस्सा लिया, जिसमें पहली बार तीन नए खेल पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो भी शामिल हैं। अबकी बार भारत ने तीरंदाजी में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। पैरालंपिक-2024 की पदक तालिका में में भारत अठारहवें स्थान पर रहा, जबकि चीन ने प्रथम, ब्रिटेन ने द्वितीय एवं अमेरिका ने तीसरा स्थान हासिल किया। पैरालंपिक में कुल 170 देशों के खिलाडियों ने हिस्सा लिया।

देश में शैक्षिक सर्वेक्षण कराएगी अभाविप

केंद्रीय कार्यसमिति बैठक में आगामी कार्ययोजना को दिया गया अंतिम रूप

■ अजीत कुमार सिंह

देश में शिक्षा क्षेत्र की स्थितियों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) एक शैक्षिक सर्वेक्षण कराने जा रही है। इस सर्वेक्षण के माध्यम से शैक्षणिक परिसरों के नीरस वातावरण एवं विद्यार्थियों की कम होती उपस्थिति, शैक्षणिक संस्थानों में रिक्त पड़े पद, फीस वृद्धि आदि से सम्बंधित वास्तविक स्थिति को सामने लाया जाएगा। शैक्षिक सर्वेक्षण कराने का निर्णय अभाविप की दो दिवसीय केंद्रीय कार्यसमिति बैठक में लिया गया।

झारखंड स्थित पारसनाथ में संपन्न केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक में खेलो भारत, सेवार्थ विद्यार्थी (एसएफएस), विकासार्थ विद्यार्थी (एसएफडी) द्वारा भारतीय खेल आधारित खेल महोत्सव, वस्त्र वितरण, बस्ती की पाठशाला, मासिक धर्म के प्रति जागरूकता हेतु ऋतुमति अभियान, पौधारोपण अभियान, स्वच्छता अभियान का आयोजन करने का निर्णय भी लिया गया। साथ ही केंद्रीय कार्यसमिति ने अहिल्याबाई होल्कर की जन्म त्रि-शताब्दी पर उनके व्यक्तित्व से युवाओं तथा विद्यार्थियों को परिचित कराने के उद्देश्य उनके जीवन पर आधारित विभिन्न कार्यक्रमों को भी अंतिम रूप दिया गया।

अभाविप की दो दिवसीय केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक का शुभांरभ राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. राजशरण शाही, राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल एवं राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान ने मां सरस्वती एवं स्वामी विवेकानंद के चित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर किया। बैठक के उद्घाटन सत्र में उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए अभाविप अध्यक्ष डा. राजशरण शाही ने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा में जैन ऋषियों तथा दार्शनिकों का योगदान विशिष्ट है। वर्तमान समय में पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दे बेहद अहम हैं। अपने आचरण से जैन मुनियों ने पर्यावरण के प्रति नागरिकों

को सचेत तथा संवेदनशील किया है। पारसनाथ जैसे विशिष्ट स्थान पर आयोजित बैठक नए दिशासूत्रों को खोजने वाली सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित पाठ्यक्रमों की दिशा में विश्वविद्यालयों को शीघ्रता से प्रयास करना होगा। शिक्षा राष्ट्र की प्रकृति और संस्कृति के अनुसार होनी चाहिए और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस दिशा में महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इसके पूर्ण क्रियान्वयन के लिए की दिशा में शीघ्रता से प्रयास होने चाहिए।

उद्घाटन सत्र में अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल ने कहा कि वर्तमान में विभिन्न परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता से जुड़े प्रश्न लगातार उठे हैं। शिक्षा की पवित्रता को बनाए रखने परीक्षा की शुचिता सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) में व्यवस्थागत परिवर्तन आवश्यक है, जिससे एजेंसी द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाएं बिना किसी समस्या के आयोजित हो सकें। उन्होंने कोचिंग क्षेत्र के नियमन को लेकर शीघ्र कदम उठाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक के प्रथम दिन पूरे देश

में आयोजित अभाविप के प्रांत अभ्यास वर्गों के दौरान विभिन्न नए प्रयोगों, पर्यावरण गतिविधियों से विद्यार्थियों से जोड़ने के लिए अभाविप के प्रयास, देश की वर्तमान शैक्षणिक तथा सामाजिक स्थिति, विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों आदि विषयों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही पेरिस ओलंपिक के दौरान महिला बॉक्सिंग मुकाबले में महिला अपमान का विषय भी बैठक में प्रमुखता से उठा।

गत 3 एवं 4 अगस्त को आयोजित दो दिवसीय बैठक में विभिन्न सांगठनिक, पर्यावरणीय, सामाजिक, तकनीकी, खेल, स्वावलंबन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चिंतन किया गया। अभाविप की देश भर में विस्तारित इकाईयों के अभियानों की संगठनात्मक समीक्षा एवं शिक्षा क्षेत्र में विभिन्न अभियानों की योजना निर्धारित हुई। साथ ही विभिन्न संगठनात्मक विषयों पर कार्यशालाओं के आयोजन द्वारा कार्यकर्ता क्षमता का विकास, पर्यावरण तथा सेवा की गतिविधियों से विद्यार्थियों से जोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार की रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन, अहिल्याबाई होल्कर की जन्म त्रि-शताब्दी के अवसर पर देशभर के शैक्षणिक संस्थानों में उनके व्यक्तित्व आधारित कार्यक्रमों के आयोजन की योजना, परिसर में उपस्थिति बढ़ाने के लिए परिसर चलो अभियान आदि विषयों पर चर्चा की गई। ■

। दिल्ली ।

डूसू कार्यालय पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का हमला अभाविप की मांग, कठोर कार्रवाई करे प्रशासन

दिल्ली विश्वविद्यालय के नार्थ कैंपस स्थित दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ कार्यालय में कांग्रेस की छात्र इकाई नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) से जुड़े कार्यकर्ताओं ने गत 14 जुलाई को डूसू अध्यक्ष, आगंतुक कक्ष, डूसू सचिव एवं सह-सचिव के कार्यालय में तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ के कारण डूसू अध्यक्ष के कार्यालय में रखी प्रभु श्रीराम की मूर्ति खंडित हो गई, जबकि वाटर डिस्पेंसर, प्रिंटर सहित अन्य सामान को नष्ट कर दिया गया।

घटना के प्रत्यक्षदर्शी गार्ड के अनुसार तोड़फोड़ से पहले कार्यकर्ताओं ने डूसू कार्यालय परिसर में अवस्थित एनएसयूआई से जुड़े डूसू उपाध्यक्ष के कमरे में बैठकर शराब पी और फिर अराजकता फ़ैलाने का काम किया। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ के इतिहास में ऐसी घिनौनी हरकत पहले भी एनएसयूआई कार्यकर्ताओं द्वारा की जाती रही है। अभाविप ने पूरे घटनाक्रम की कड़ी निंदा करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन एवं दिल्ली पुलिस से मांग की है कि घटनाक्रम में शामिल आपराधिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए कदम उठाए।

अभाविप दिल्ली के प्रदेश मंत्री हर्ष अत्री के अनुसार अभाविप ने मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय कुलपति तथा दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करके मांग की है कि प्रकरण में लिप्त डूसू उपाध्यक्ष अभि दहिया एवं अन्य कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके न्यायोचित कार्रवाई करे। साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन डूसू उपाध्यक्ष अभि दहिया को डूसू उपाध्यक्ष पद से हटाने के लिए कदम उठाए। दोषियों पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए अभाविप ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन भी सौंपा है।

अभाविप ने दिल्ली विश्वविद्यालय स्थित मॉरिस नगर थाने में दोषियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराकर दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने एवं डूसू उपाध्यक्ष को पद से हटाने की मांग भी की है। अभाविप का मानना है कि विश्वविद्यालय परिसर में ऐसी घटना का होना छात्रों के लिए चिंता का विषय है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष तुषार डेढ़ा के अनुसार दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ कार्यालय में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई तोड़फोड़ शर्म की बात है। इससे एनएसयूआई का असली चेहरा भी सामने आ गया है। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने की आवश्यकता

आठवें राष्ट्रीय सम्मेलन में कृषि वैज्ञानिकों को किया गया पुरस्कृत

विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए कृषि क्षेत्र में नवाचार की आवश्यकता है। इसके लिए गंभीरता से प्रयास करने होंगे। कृषि क्षेत्र में नवाचार की भूमिका को इंगित करते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप-महानिदेशक डा. तिलक राज शर्मा ने एग्रीविज़न के आठवें राष्ट्रीय सम्मेलन में एग्रीवीज़न की विशिष्टता को संदर्भित करते हुए कहा कि स्वतंत्रता के बाद देश में हरित उत्पादन, खाद्य उत्पादन एवं बीज उत्पादन में अभूतपूर्व बढ़ोत्तरी हुई है। लेकिन बदलती परिस्थियों को देखते हुए कृषि क्षेत्र में नवाचार की प्रबल आवश्यकता है। नवाचार के माध्यम से कृषि क्षेत्र से जुडी समस्यायों का समाधान बहुत ही आसानी से किया जा सकता है।

राजधानी दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सभागार में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के आयाम एग्रीविज़न के दो दिवसीय आठवें राष्ट्रीय सम्मेलन में "विकसित भारत में कृषि का योगदान : विजन - 2047" विषय पर चर्चा की गई। सम्मेलन में अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान ने एग्रीविज़न की सार्थक यात्रा में एग्रीविज़न के छात्रों के योगदान की चर्चा करते हुए कहा कि यह उनके संघर्ष, मंथन, चिंतन एवं सकारात्मक चिंतन के साथ किए गए कार्य की यात्रा है। स्वतंत्रता के बाद समाज के हर क्षेत्र में सतत विकास हेतु लगातार नीतियां बनीं लेकिन कृषि क्षेत्र की नीति निर्माताओं ने अनदेखी की। 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य प्राप्ति की ओर जब बढ़ रहे हैं, तो कृषि विमर्श पर ध्यान देना ही होगा, तभी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे।

उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में परिवर्तन के लिए युवाओं को स्टार्टअप इको सिस्टम पर विचार करना होगा। कृषि आज भी सामान्य वर्ग से आने वाले व्यक्ति के लिए अकेला साधन बचा है, जिसके माध्यम से वह आगे बढ़ सकता है। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी 49 प्रतिशत होना यह प्रदर्शित करता है कि महिलाओं की भागीदारी सिर्फ़ घर के कार्यों तक सीमित नहीं है। वह आगे बढ़कर समाज के हर क्षेत्र

में अपना योगदान दे रही हैं।

सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप-महानिदेशक (कृषि शिक्षा) डा. राकेश चंद्र अग्रवाल ने एग्रीविजन के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि कृषि विश्वविद्यालयों में छात्राओं का प्रतिशत गत आठ वर्षों में 23 प्रतिशत से बढ़कर 49.3 प्रतिशत हो गया है। एग्रीविजन ने कृषि क्षेत्र में क्या विजन होना चाहिए? इसके लिए एक मंच तैयार किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं।

सम्मेलन में डा. राजेन्द्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विद्यालय (समस्तीपुर) के कुलगुरु पी. एस. पांडेय ने कृषि क्षेत्र में ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता पर जोर दिया, जो देश के मूल्यों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम हो। उन्होंने कहा कि प्राचीन कृषि तकनीकों और नई तकनीकों में समावेश करके विकसित भारत की संकल्पना को साकार किया जा सकता है। सम्मेलन के पहले दिन एग्रीविज़न के राष्ट्रीय संयोजक शुभम सिंह पटेल ने एग्रीविज़न के कार्यों की चर्चा करते कृषि क्षेत्र में नई तकनीक के समावेश और निरंतर कृषि को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया।

इतिहास पर विचार किए बिना भविष्य खड़ा नहीं हो सकता : आकांत

सम्मेलन के दूसरे दिन 'विकसित भारत की संकल्पना' विषय पर अपने विचार रखते हुए अभाविप के निवर्तमान राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री प्रफुल्ल आकांत ने कहा कि एग्रीविजन प्रतिवर्ष कृषि शिक्षा, कृषि हित एवं भारत हित से जुड़े विषयों पर मंथन करता है, जिसमें छात्र, शिक्षक, विशेषज्ञ, वैज्ञानिक सहित वह सभी लोग शामिल होते हैं, जो कृषि क्षेत्र में होने वाले सकारात्मक परिवर्तन में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं।

उन्होंने इतिहास से सीखने का आह्वान करते हुए कहा कि इतिहास पर विचार किए बिना भविष्य खड़ा नहीं हो सकता है। भारत के समृद्ध इतिहास में ऐसे अनेक तथ्य है जो यह बताते हैं कि सहभागिता और सामूहिकता के माध्यम से भारतवर्ष में बदलाव लाया जा सकता है। इसके लिए नवाचार, संस्थागत विकास, प्रेरणा, अधोसंरचना, व्यक्तिगत सहभागिता एवं संस्कृति पर विचार करके कार्य करना ही होगा। सम्मेलन में अभाविप की राष्ट्रीय मंत्री शिवांगी खरवाल ने भी एग्रीविजन के कार्यों, उद्देश्यों एवं आगामी योजनाओं पर अपने विचार रखे। गत 20 एवं 21 जुलाई को आयोजित सम्मेलन में डा. सीमा जग्गी, डा. पी. ब्रह्मानंद, डा. श्यामाकांत मुंजे. डा. गोपाल ठाकरे और नीरज कुमार प्रजापति को उनके विशेष योगदान के लिए वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

उत्तर प्रदेश

मेधावी छात्रों को अभाविप ने किया सम्मानित

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) बरेली महानगर ने मेधावी छात्रों को सम्मानित करने के लिए एक समारोह का आयोजन किया। प्रतिभा सम्मान समारोह में 1195 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने हाई स्कूल में 75 प्रतिशत से अधिक एवं इंटरमीडिएट में 70 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल किए किए हैं। मेधावी छात्रों को सम्मानित करने के लिए नगर के संजय गांधी कम्युनिटी सभागार में आयोजित समारोह का शुभारंभ प्रदेश सरकार की मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्या ने किया। इस अवसर पर अभाविप राष्ट्रीय कार्यकारिणी के विशेष आमंत्रित सदस्य प्रो. भूपेन्द्र सिंह , प्रांत सह मंत्री अवनी यादव, विशिष्ट अतिथि महापौर डा. उमेश गौतम एवं निहाल सिंह लोधी, अभाविप महानगर अध्यक्ष विकास शर्मा, कार्यक्रम अध्यक्ष प्रो. पवन शर्मा, कार्यक्रम संयोजक श्रेयांश वाजपेई, जिला सह-संयोजक शुभ गंगवार एवं महानगर मंत्री आनंद कठेरिया भी उपस्थित रहे।

समारोह में कैबिनेट मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्या ने कहा कि छात्र किसी भी देश के स्वर्णिम भविष्य का सृजनकर्ता होता है। उसे अनुशासित, जागरूक और सजग रहने की अति आवश्यकता पड़ती है। उनका सौभाग्य है कि वह स्वयं छात्र जीवन मे अभाविप की कार्यकर्ता रही हैं, जिसने जीवन मूल्यों को सिखाते हुए राष्ट्रहित में कार्य करने की प्रेरण दी।

सम्मानित किए गए छात्रों को प्रमाण पत्र प्रदान करके उन्होंने कहा कि प्रतिभाशाली छात्रों ने बरेली में अपना नाम रोशन किया है। उम्मीद है कि मेधावी छात्र भविष्य में देश का नाम रोशन करेंगे। समारोह में मुख्य वक्ता एवं अभाविप राष्ट्रीय कार्यकारिणी के विशेष आमंत्रित सदस्य प्रो. भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि अभाविप विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, जिसने छात्र-हित से लेकर भारत के व्यापक हित से संबंधित समस्याओं की ओर बार-बार ध्यान दिलाया है। प्रान्त सहमंत्री अवनी यादव ने छात्रों से कहा कि आप ही नव भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाकर समाज जीवन के अभिन्न अंग होंगे।

कार्यक्रम अध्यक्ष प्रो. पवन शर्मा ने कहा कि शिक्षा से लेकर समाज सेवा और सामाजिक उत्थान तक अभाविप की उल्लेखनीय भूमिका रही है। समारोह में महापौर उमेश गौतम, निहाल सिंह लोधी ने भी अभाविप की अनुकरणीय भूमिका का उल्लेख करते हुए रचनात्मक कार्य करने के लिए छात्रों का आह्वान किया। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

'विश्व में परचम लहराएं चिकित्सा विद्यार्थी'

सातवां ऑल इंडिया मेडिकल एंड डेंटल स्टूडेंट सम्मेलन लखनऊ में संपन्न

भारत में शिक्षा के स्वरूप में परिवर्तन होना अति आवश्यक है। जब तक देश में शिक्षा का स्वरूप नहीं बदलेगा और तकनीकी की बेहतर समझ नहीं होगी, तब तक हमारा मार्ग हमें अपनी मंजिल से दिग्भ्रमित करता रहेगा। शिक्षा में बदलाव की भूमिका को इंगित करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने चिकित्सा विद्यार्थियों को चिकित्सा को भगवान स्वरूप मानकर अपना कार्य करने की का सन्देश दिया। वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के आयाम मेडिविजन द्वारा आयोजित सातवें ऑल इंडिया मेडिकल एंड डेंटल स्टूडेंट सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

सम्मेलन में उपस्थित चिकित्सा विद्यार्थियों को राष्ट्र के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करते हुए उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि चिकित्सा विज्ञान के विद्यार्थियों को संपूर्ण जगत में परचम लहराने की आवश्यकता है क्योंकि चिकित्सा विज्ञान के माध्यम से ही किसी भी बीमारियों से लड़कर जीतने की क्षमता रखते हैं।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के अटल सभागार में आयोजित सम्मेलन का आरंभ कोलकाता स्थित आरजीकर मेडिकल कालेज में निर्ममता का शिकार हुई स्नातकोत्तर की दिवंगत छात्रा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ हुआ।

सम्मेलन में मेडिविजन के कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए अभाविप के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. राजशरण शाही ने कहा कि भारत की शिक्षा व्यवस्था उसकी संस्कृति से जुड़ी होनी चाहिए। विविधताओं में एकता की पहचान करने वाला देश भारत है। विविधता

में एकता का अर्थ यह है कि कई तरह की भिन्नताओं के बावजूद एक साथ रहना। धार्मिक, सांस्कृतिक, जातिगत, आस्था, भाषा, क्षेत्रीय मतभेद, और समाज में कई अन्य कारक इन विविधताओं में योगदान कर सकते हैं।

सम्मेलन में राष्ट्रीय मंत्री डा. वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि मेडिविजन अभाविप के स्थापना काल से ही लोगों के बीच काम करते आया है। मेडिविजन कार्यकर्ताओं ने हमेशा से ही चिकित्सा के क्षेत्र में अपना सम्पूर्ण समर्पण देकर लोगों को सहायता पहुंचाकर उनके उत्तम स्वास्थ एवं सफल जीवन व्यतीत करने में उनका सहयोग किया है। मेडिविजन के राष्ट्रीय संयोजक डा. अभिनंदन बोकरिया ने विश्व बंधुत्व की कामना का उद्घोष करते हुए कहा कि कोरोना काल में भी भारत ने विश्व बंधुत्व की भावना को चरितार्थ करते हुए लोगों को उनकी विसंगतियों से बाहर निकाला है और हम स्वामी विवेकानन्द के सपनों वाला भारत बनाने की कामना करते हुए कार्य कर रहे हैं।

ऑल इंडिया मेडिकल एंड डेंटल स्टूडेंट सम्मेलन के समापन अवसर पर मेडिविज़न के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान ने कहा कि आयुर्वेद का मुख्य लक्ष्य व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना एवं रोगी हो जाने पर उसके विकार का प्रशमन करना है। ऋषि जानते थे कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति स्वस्थ जीवन से है। इसीलिए उन्होंने आत्मा के शुद्धिकरण के साथ शरीर की शुद्धि एवं स्वास्थ्य पर भी विशेष बल दिया है। आयुर्वेद की प्राचीनता वेदों के काल से ही सिद्ध है। मूल रूप से मौखिक परंपरा के रूप में साझा की जाने वाली आयुर्वेद को पांच हजार वर्ष से भी पहले संस्कृत में चार पवित्र ग्रंथों में दर्ज किया गया था, जिन्हें वेद कहा जाता है।

समापन दिवस के विशिष्ठ अतिथि एवं किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय की कुलपति सोनिया नित्यानंद ने मेडिविजन को एक ऐसा संगठन बताया, जो चिकित्सकीय प्रतिभाओं को परख कर उन्हें उचित स्थान देता है। उन्होंने कहा कि अगर भारत को स्वस्थ बनाना चाहते हैं तो हमें खुद को स्वस्थ बनाना होगा। चिकित्सा क्षेत्र में आयुर्वेद का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इसकी मदद से बीमारी को जड़ से खत्म करने में सफलता मिली है। सम्मेलन में मेडिविजन के अखिल भारतीय प्रमुख आशीष चंदेल ने भी मेडिविजन कार्यकर्ताओं का सम्बोधित किया

जानकारी हो कि गत 27 एवं 28 अगस्त को आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक, अभाविप के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. राज शरण शाही, राष्ट्रीय मंत्री डा. वीरेंद्र सिंह सोलंकी, मेडिविजन के राष्ट्रीय संयोजक डा. अभिनंदन बोकरिया ने माता सरस्वती एवं स्वामी विवेकानन्द के चित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन के किया। दो दिवसीय सम्मेलन का संचालन मेडिविज़न की केजीएमयू इकाई की प्रमुख डा. शिविली राठौर ने किया। सम्मेलन में अभाविप पदाधिकारियों के साथ ही बड़ी संख्या में भारत एवं नेपाल के चिकित्सा विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

प्रिय मित्रों !

शिक्षा - क्षेत्र की प्रतिनिधि - पत्रिका के रूप में 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' अगस्त-सितम्बर संयुक्तांक 2024 अंक आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। यह अंक महत्वूर्ण लेख एवं विभिन्न समसामयिक घटनाक्रमों व खबरों को समाहित किए हुए हैं। आशा है, यह अंक आपके आवश्यकताओं के अनुरूप उपादेय साबित होगा। कृपया 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' से संबंधित अपने सुझाव व विचार हमें नीचे दिए गए संपादकीय कार्यालय के पते अथवा ई - मेल पर अवश्य भेजें : -

'राष्ट्रीय छात्रशक्ति'
26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नई दिल्ली - 110002.
फोन : 011-23216298
www.chhatrashakti.in
rashtriyachhatrashakti.abvp@gmail.com
www.facebook.com/Rchhatrashakti
www.twitter.com/Rchhatrashakti
www.instagram.com/ Rchhatrashakti

कांवड़ियों के लिए सेवा शिविर

झारखंड स्थित देवघर में बाबा बैद्यनाथ में जलार्पण के लिए आने वाले कांवड़ियों के सेवार्थ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के आयाम सेवार्थ विद्यार्थी (एसएफएस) द्वारा सेवा शिविर लगाया गया। शिविर का शुभारंभ अभाविप के राष्ट्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम विश्व प्रसिद्ध है और यहां प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ऐसे श्रद्धालुओं की सेवा में एसएफएस सेवा शिविर एक सकारात्मक पहल है। झारखंड प्रांत के प्रांत सहमंत्री शुभम राय ने बताया कि अभाविप हर वर्ष विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला में कांवड़ियों के लिए सेवा कार्य करती है। सेवाकार्य में विभिन्न प्रकार के फलों का वितरण, जल व्यवस्था एवं मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

जानकारी हो कि सेवा परमो धर्मः के मूलमंत्र को लेकर पूर्ण श्रद्धा से सेवार्थ विद्यार्थी के कार्यकर्ता सेवा कार्य करते हैं। श्रावण मास में कांवड़ यात्रा एक पुण्यदायी तीर्थयात्रा मानी गई है, जो भगवान शिव के भक्तों के लिए बहुत महत्व रखती है। यह यात्रा सावन के प्रथम दिन से आरम्भ शुरू हो जाती है। इस आध्यात्मिक यात्रा में गंगा नदी से पवित्र जल लेकर कई किलोमीटर की पैदल यात्रा तय कर श्रद्धालु उस जल को शिव मंदिरों में चढ़ाते है। इस दौरान सेवार्थ विद्यार्थी के कार्यकर्ता देश के विभिन्न स्थानों पर निःशुल्क सेवा शिविर के माध्यम से श्रद्धालुओं को हर प्रकार की सेवा प्रदान करने का प्रबंध करते हैं। इस वर्ष भी कावड़ियों के लिए विभिन्न स्थानों पर सेवा शिविर लगाकर सेवा कार्य किया गया।

उत्तर प्रदेश स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर में जल चढ़ाने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के मध्य सेवार्थ विद्यार्थी कार्यकर्ताओं ने नींबू शर्बत और चना का प्रसाद का वितरण किया गया। दिल्ली, मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, हरिद्वार सहित कई स्थानों में श्रावण माह के दौरान निःशुल्क सेवा शिविर लगाकर कांवड़ यात्रियों को सेवा प्रदान की। इस दौरान हजारों कांवड़ियों को निशुल्क स्वास्थ्य सेवा का लाभ मिला।

जिज्ञासा सेवा कार्य

अभाविप मेरठ प्रांत के जिज्ञासा आयाम ने गत 4 अगस्त को नोएडा स्थित भाउराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर में प्राण प्रत्यागमन कार्यक्रम का आयोजन किया। लगभग सौ बच्चों की उपस्थित में हुए कार्यक्रम में पांच सत्र हुए। कार्यक्रम में डा. घनश्याम वत्स ने प्राण प्रत्यागमन, डा. सुनेत्री ने आयुर्वेद, डा. अमित अग्रवाल ने भारतीय चिकित्सा पद्धति के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में उपस्थित सभी छात्र और छात्राओं को प्रमाणपत्र देकर सम्मानित भी किया गया। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

छात्राओं में कौशल विकास के लिए सर्जना निखार शिविर

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) द्वारा दरभंगा में आयोजित सर्जना निखार शिविर का समापन गत 6 अगस्त को हुआ। शिविर के माध्यम से छात्राओं को कई विधाओं में कौशल विकास का अवसर प्राप्त हुआ। शिविर के समापन पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पूजा कश्यप ने बताया कि सर्जना निखार शिविर का आयोजन गत अठारह वर्षों से हो रहा है। इसके माध्यम से छात्राओं को कई विधाओं में कौशल शिक्षा देकर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने का काम किया जा रहा है। इस वर्ष शिविर का आयोजन गत 3 जून से 3 जुलाई के मध्य किया गया।

शिविर के समापन अवसर पर आयोजित समारोह में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव कुमार पंडित ने सर्जना निखार शिविर की सराहना करते हुए कहा कि समाज की महिलाओं के कौशल विकास से ही अभाविप का ध्येय राष्ट्र निर्माण को पूरा किया जा सकता है। इस अवसर पर परीक्षा नियंत्रक विनोद कुमार ओझा ने कहा कि वर्तमान समय में स्वरोजगार स्वावलंबन पर बात तो सभी जगह हो रही है, लेकिन इसका जीवंत उदाहरण सर्जना निखार शिविर के रूप में देखा जा सकता है।

समारोह में उत्तर बिहार प्रांत संगठन मंत्री धीरज कुमार ने कहा कि भारत की संस्कृति में प्रारंभ से ही स्त्रियों के प्रति अत्यंत आदरणीय दृष्टिकोण रहा है। पुरातन काल से ही भारत में स्त्रियों को अत्यधिक पवित्र एवं पुनीत समझा जाता रहा है। अभाविप का यह सर्जना निखार शिविर स्त्रियों के कौशल को बाहर लाने का एक प्रयास है। जिला प्रमुख बिंदु चौहान ने सभी छात्राओं की प्रशंसा करते हुए शिविर के सफल आयोजन के लिए उन्हें बधाई दी। जानकारी हो कि गत अठारह वर्ष के दौरान सर्जना निखार शिविर के माध्यम से 7500 से अधिक छात्राओं एवं गृहणियों को प्रशिक्षित किया गया, जिसमें से 830 से अधिक आत्मनिर्भर बनी। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

। स्मृति शेष ।

वरिष्ठ पत्रकार उमेश उपाध्याय के निधन से अपूरणीय क्षति : अभाविप

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने 66 वर्ष की आयु में वरिष्ठ पत्रकार उमेश उपाध्याय की आकस्मिक मृत्यु पर गहन दुःख व्यक्त किया है। अभाविप ने उनके निधन को पत्रकारिता जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति बताया है।

अभाविप के पूर्व कार्यकर्ता एवं ख्यातिप्राप्त वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय उमेश उपाध्याय की गत 1 सितंबर को एक दुर्घटना में असामयिक निधन हो गया था। दुर्घटना वाले दिन वह राजधानी दिल्ली के वसंत कुंज स्थित अपने आवास में हो रहे निर्माण कार्य के दौरान छत से नीचे गिर गए थे, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई। बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका और उनका निधन हो गया।

मूल रूप से उत्तर प्रदेश स्थित निवासी स्वर्गीय उपाध्याय ने कई मीडिया संगठनों में महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन किया। मीडिया क्षेत्र में चार दशक से अधिक समय तक सक्रिय

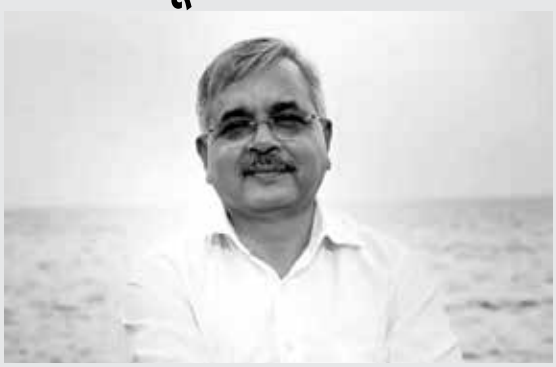

रहे स्वर्गीय उपाध्याय पत्रकारिता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए पहचाने जाते रहे हैं। पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

ममता राज में प्रशिक्षु महिला डाक्टर की निर्मम हत्या

अभाविप ने किया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन, आरोपी को फांसी देने की मांग

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता स्थित आरजी कर मेडिकल कालेज में एक प्रशिक्षु महिला डाक्टर की बलात्कार के बाद निर्मम हत्या की घटना से पूरा देश सदमे में है। चेस्ट मेडिसिन विभाग की स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष की छात्रा और प्रशिक्षु डाक्टर के साथ हुई निर्ममता के विरोध में पश्चिम बंगाल से लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में धरना-प्रदर्शन करके दोषी को कठोरतम सजा देने की मांग कर रहे हैं। प्रशिक्षु महिला डाक्टर के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी के साथ ही मेडिकल कालेज के पूर्व प्रधानाचार्य डा. संदीप घोष को गिरफ्तार किया जा चुका है।

पश्चिम बंगाल में घटित जघन्यतम श्रेणी के इस अपराध ने पूरे देश को झकझोर दिया। ऐसा पहली बार हुआ जब पश्चिम बंगाल में दुष्कर्म और निर्मम हत्या के मामले में क्रोधित देश की जनता सड़क पर उतर आई। पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, उड़ीसा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में समाज के हर वर्ग के लोगों ने स्वतः विरोध-प्रदर्शन में हिस्सा लेकर ममता सरकार के प्रति अपना क्षोभ व्यक्त किया। राज्य में अपनी सरकार की खामियों, कमियों और कुप्रशासन को स्वीकार करने के स्थान पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी

आरजी कर मेडिकल कालेज में हुई घटना से द्रवित हुईं राष्ट्रपति

कोलकाता स्थित आरजीकर मेडिकल कालेज में एक महिला डाक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि घटना से वह निराश और भयभीत हैं। अब बहुत हो गया, अब समय आ गया है कि भारत महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की 'विकृति' के प्रति जागकर उस मानसिकता का मुकाबला करे जो महिलाओं को कम शक्तिशाली, कम सक्षम, कम बुद्धिमान के रूप में देखती है। सबसे अधिक हताश करने वाली बात यह है कि यह केवल एक अकेला मामला नहीं है। यह महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की कड़ी का एक हिस्सा है।

एक समाचार एजेंसी के माध्यम से कोलकाता में हुई वीभत्स घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि इतिहास का सामना करने से डरने वाले समाज सामूहिक भूलने की बीमारी का सहारा लेते हैं। अब समय आ गया है कि भारत इतिहास का सामना करे। हमें इस विकृति से व्यापक तरीके से निपटना चाहिए ताकि इसे शुरू में ही रोका जा सके। जो लोग इस तरह के विचार रखते हैं, वह महिलाओं को एक वस्तु के रूप में देखते है। अपनी बेटियों के प्रति यह हमारा दायित्व है कि हम उनके भय से मुक्ति पाने के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करें। कोई भी सभ्य समाज बेटियों और बहनों के खिलाफ इस तरह के अत्याचार की इजाजत नहीं दे सकता। देश को इस पर गुस्सा जाहिर करना ही चाहिए और मैं भी इससे गुस्से में हूं।

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

महिलाओं के लिए निर्मम पश्चिम बंगाल

■ याज्ञवल्क्य शुक्ल

प्रसिद्ध चिकित्सक, परोपकारी एवं स्वतंत्रता संग्रामी राधा गोविंदकर के नाम वाले मेडिकल कालेज में महिला अस्मिता के मर्दन से पूरा भारतीय समाज द्रवित है। बहन निर्भया के आंसुओं का ताप मध्यम भी नहीं हुआ था कि पश्चिम बंगाल के आरजी कर मेडिकल कालेज की डाक्टर बहन के साथ घटित घटना से आम जनमानस हृदय उद्वेलित एवं गुस्से में है। सभ्य मानव समाज में महिला अस्मिता से जुडी घटना के के लिए हम सभी सामूहिक रूप से नैतिक जिम्मेदार हैं। सामूहिक नैतिक जिम्मेदारी इसलिए है क्योंकि हम उस सामाजिक वातावरण को निर्माण करने में विफल रहे जो आरजी कर मेडिकल कालेज जैसी घटना को घटित होने से रोक सकता था।

पूरा भारतीय समाज सामूहिक रूप से नैतिक जिम्मेदार हो सकता है, परंतु उस व्यक्तिगत एवं संस्थागत कानूनी जिम्मेदारी का क्या? नारी शक्ति की उपासना के तीर्थस्थल पश्चिम बंगाल में आए दिन सुनियोजित ढंग से महिलाओं के साथ होने वाली शर्मनाक घटनाओं में शर्म एवं चिंता की विषय यह है कि अधिकांश मामलों में उस सरकार की संलिप्तता पाई जा रही है, जिसकी मुखिया स्वयं एक महिला हैं। वह राज्य की मुख्यमंत्री होने के साथ-साथ गृह मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री पद को भी संभाल रही हैं। तृणमूल कांग्रेस द्वारा नारी वेदना को नौटंकी की संज्ञा देने, उसके चरित्र पर प्रश्न उठाने एवं उसे सत्ता के भोग की वस्तु समझने का ही परिणाम है आरजीकर मेडिकल कालेज की घटना। ऐसी परिस्थिति में एक आम महिला की यह आशा कि वह राज्य में सुरक्षित है, बेमानी लगता है।

वास्तव में पश्चिम बंगाल की ममता सरकार राज्य में न्यूनतम कानून-व्यवस्था लागू करने में भी विफल हो चुकी हैं। महिला शोषण के लिए कुख्यात व्यक्ति को 'सिविक वॉलंटियर' के छद्म नाम से नौकरी देने वाली ममता सरकार अपने बचाव में जिस तरह के तर्क दे रही है, वह शर्म का विषय है। तृणमूल कांग्रेस द्वारा महिला उत्पीड़न के विरोध में आयोजित देशव्यापी विरोध-प्रदर्शन को कुनामित करने एवं उन पर बल प्रयोग करने के कारण आम जनमानस दर्द एवं क्रोध में है। आज पश्चिम बंगाल ना तो माताओं-बहनों के लिए सुरक्षित बचा है, और ना ही उन नागरिकों के लिए जो उन माताओं-बहनों की अस्मिता की रक्षा हेतु उनकी आवाज़ बनकर सड़क पर उतरे हैं। संदेशखाली की महिलाएं भी अब तक न्याय की आस में आंख खोल कर सोने को विवश हैं।

आरजी कर मेडिकल कालेज की घटना एक बानगी मात्र है। राज्य में प्रतिदिन महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध में सत्ता संरक्षित गुंडों की संलिप्तता से समझा जा सकता है कि एक घटना की जांच सीबीआई को सौंपने मात्र से महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराधों को रोका नहीं जा सकता है। राज्य के जनता न्याय के लिए केंद्र सरकार से गुहार लगा रही हैI समय आ गया है कि केंद्र सरकार संविधान प्रदत्त शक्तियों का उपयोग कर राज्य में कानून-व्यवस्था की पुनर्स्थापना के लिए यथाशीघ्र आवश्यक कदम उठाए, जिससे राज्य की जनता को सत्ता संरक्षित अपराधियों से बचाया जा सकेगा। ■

ने आम जनता के क्रोध को दबाने के लिए हर संभव प्रयास किया। मामले को लेकर राज्य पुलिस और राज्य सरकार की भूमिका पर न्यायालय ने भी प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए हैं।

घटना के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने राजधानी दिल्ली स्थित बंगभवन सहित देशव्यापी प्रदर्शन करते हुए ममता सरकार की भर्त्सना करते हुए न्याय की मांग की। गत 17 अगस्त को अभाविप के देशव्यापी धरना-प्रदर्शन में लाखों की संख्या में अभाविप कार्यकर्ता, विद्यार्थी एवं आम लोग सम्मिलित

हुए और प्रशिक्षु महिला डाक्टर के साथ हुई क्रूरतम घटना पर रोष प्रकट किया। अभाविप कार्यकर्ताओं ने दोषियों को फांसी की सजा देने के साथ ही छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की मांग की।

राजधानी दिल्ली में अभाविप के प्रदर्शन के दौरान अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल ने घटना को हृदय विदारक बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने राज्य में महिलाओं की सुरक्षा करने में असफल रही हैं। इसलिए उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाली अभाविप की राष्ट्रीय मंत्री शिवांगी खरवाल ने कहा कि पश्चिम बंगाल की कानून-व्यवस्था बदतर हो चुकी है। मेडिकल कालेज में हुई घटना के बाद जिस प्रकार साक्ष्य मिटाने का प्रयास हुआ और पुलिस मूकदर्शक बनी रही, वह राज्य सरकार की कानून-व्यवस्था के प्रति उदासीनता को दिखाती है।

प्रदर्शन करने वाली छात्राओं ने घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसा पहली बार नहीं है, जब पश्चिम बंगाल में इस तरह की जघन्य घटना हुई है। राज्य के संदेशखाली में हुई घटना से सभी परिचित हैं। बंगाल में महिलाओं एवं छात्राओं की सुरक्षा के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है और ममता सरकार अपनी कमियों को स्वीकार करने की जगह दोषियों को बचाने का प्रयास कर हुई है। प्रदर्शनकारी छात्राओं ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बंगाल में अपराधी ममता बनर्जी की शरण में हैं। आरोपियों को उनका संरक्षण प्राप्त है। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

। केरल ।

न्यायमूर्ति हेमा समिति ने वामपंथी शासन के कु-कर्मों को किया उजागर

केरल में वामपंथी शासन के कु-कर्मों को उजागर करने वाला एक नया कारनामा मलयालम फिल्म उद्योग पर केंद्रित न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट से सामने आया है। यह रिपोर्ट फिल्म अभिनेत्रियों के साथ हुए यौन शोषण, यौन दुर्व्यवहार और दुष्कर्म पर केंद्रित है। रिपोर्ट में सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के विधायक एवं अभिनेता एम. मुकेश, जयसूर्या और मनियानपिल्ला राजू सहित कई बड़े अभिनेताओं और फिल्मकारों पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद यौन उत्पीड़न के अठारह मामले दर्ज हो चुके हैं, जिनमें माकपा विधायक एम. मुकेश सहित अन्य दो आरोपियों के विरुद्ध दुष्कर्म का मामला शामिल है। राज्य में वामपंथी क्रियाकलापों को उजागर करने वाले इस मामले में केरल की एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट्स (एएमएमए) के कई सदस्यों की संलिप्तता पाए जाने के बाद एएमएमए अध्यक्ष का पद संभाल रहे अभिनेता मोहनलाल सहित अन्य पदाधिकारियों ने अपने पदों से इस्तीफा भी दे दिया है।

मलयालम फिल्म उद्योग में महिला अभिनेत्रियों और मॉडलों के यौन शोषण और उत्पीड़न से जुड़े मामलों की जांच के लिए 2017 में केरल उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति के. हेमा की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। वूमेन इन सिनेमा कलेक्टिव की याचिका पर गठित न्यायमूर्ति के. हेमा समिति ने दिसंबर 2019 में अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को सौंप दी थी।

मुख्यमंत्री को सौंपी गई रिपोर्ट लगभग पांच वर्ष बाद गत 19 अगस्त को सार्वजनिक हुई, जिसमें महिला कलाकारों के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न, भेदभाव और शोषण की कड़ी निंदा की गई है। रिपोर्ट में नामित अपराधियों के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई की मांग को लेकर केरल उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका भी दाखिल की गई है, जिस पर गत 22 अगस्त को सुनवाई के बाद न्यायालय ने राज्य सरकार को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

कोलकाता में प्रशिक्षु डाक्टर की निर्मम हत्या के विरुद्ध अभाविप का देशव्यापी प्रदर्शन

কोलकाता, पं बंगाल

भोपाल, मध्यप्रदेश

पिंपरी चिंचवाड़, महाराष्ट्र

पुदुचेरी

गुंटुर, आंध्रप्रदेश

इम्फाल, मणिपुर

RNI NO.: DELBIL/2017/73636
DATE OF POSTING: 10-11 SEPTEMBER, 2024
DATE OF PUBLISHING: 8 SEPTEMBER, 2024

POST OFFICE: NDGPO, NEW DELHI
POSTING REGISTRATION NO. DL(C)-11/1409/2024-26

दत्ताजी डिडोलकर जन्मशती वर्ष

कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए रा. स्व. संघ के सरसंचालक डा. मोहन भागवत, देवनाथ मठ के स्वामी जितेन्द्रनाथ महाराज, आधारवड पुस्तक के लेखक अरुण करमकर, संयोजक भुपेन्द्र शहाणे, केंद्रीय मंत्री नीतिन गडकरी, अभाविप राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान एवं स्वागत समिति मंत्री अजय संचेती।

दत्ताजी डिडोलकर पर आधारित 'आधारवड' पुस्तक का विमोचन करते हुए रा.स्व.संघ के सरसंघचालक डा. मोहन भागवत (मध्य), केंद्रीय मंत्री नीतिन गडकरी, अभाविप राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान, स्वागत समिति मंत्री अजय संचेती, स्वामी जितेन्द्र महाराज, लेखक अरुण करमकर एवं संयोजक भुपेन्द्र शहाणे।